RNI No. DLHIN/25/A2321

DD

दिव्य दिल्ली

दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

वर्ष: 01, अंक: 08, पृष्ठ: 08

infodivyadelhi@gmail.com

शुक्रवार, 05 सितम्बर, 2025 तदनुसार 19 भाद्रपद विक्रमी सम्वत 2082 | www.divyadelhi.com | facebook.com/divyadelhi

तापमान अधिकतम 30 डिग्री न्यूनतम 25 डिग्री

सूयोदय 05.25 | सूर्यास्त 06.50

रेड अलर्ट! दिल्ली में बेकाबू बाढ़, सचिवालय में घुसा पानी

- यमुना के पानी में डूबा उस्मानपुर गांव
- कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर जलभराव
- निगमबोध घाट बंद

राजेश चौहान

नई दिल्ली

यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं। अब शहर के भीतरी हिस्सों में भी पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। वहीं, हथिनीकुंड बैराज से बुधवार सुबह से लेकर रात तक छोड़े जा रहे पानी को दिल्ली आते देखकर ये साफ है कि पानी जल्द कम नहीं होगा। देर रात यमुना का जलस्तर 207.40 मीटर तक पहुंच गया था। केंद्रीय जल आयोग ने सूचना जारी की है कि दिल्ली में पानी और बढ़ सकता है। इससे आशंका है कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208 मीटर तक पहुंच सकता है। यदि ऐसा होता है तो 2023 की बाढ़ की तरह आउटर रिंग रोड और कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक पानी पहुंचने के आसार हैं। इससे दिल्ली में न केवल आवागमन बाधित हो सकता है बल्कि बड़े पैमाने पर जनजीवन प्रभावित होने का खतरा भी है।

लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर

मयूर विहार-फेज 1 के पास बनाए गए राहत शिविरों में पानी

वहीं, दिल्ली में लगातार बारिश और यमुना नदी में उफान की वजह से मयूर विहार-फेज 1 के पास बनाए गए राहत शिविरों में पानी भर गया है। दिल्ली के सिविल लाइंस में बेला रोड पर उफनती यमुना नदी का पानी कीचड़, पानी और ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर ये परिवार अपने आशियाने को खोने के डर से सहमे हुए हैं। यही नहीं रात में वर्षों की मेहनत की कमाई और घर के सामान को बचाने के लिए रातभर जागने को मजबूर हैं। शरणार्थी राहुल सिंह ने बताया कि घरों तक पानी पहुंच गया है। प्रशासन ने न टेंट दिए और न ही खान-पान की ठीक व्यवस्था है।

निगमबोध घाट डूबा, अंतिम संस्कार पर रोक

यमुना के जलस्तर का असर राजधानी के सबसे बड़े श्मशान घाट निगमबोध पर भी पड़ा है। बुधवार शाम को पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आने से यहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रोक दी गई है। घाट परिसर में कई फीट तक पानी भर गया है। यमुना का पानी बहकर रिंग रोड तक पहुंच गया है। प्रशासन ने निगमबोध घाट को बचाने के लिए कई प्रयास किए। यमुना की ओर मिट्टी भरकर बोरे लगाकर पानी को रोकने की कोशिश की गई लेकिन पानी के बढ़ते दबाव के आगे यह प्रयास नाकाम साबित हुए। घाट की एक तरफ दीवार का कुछ हिस्सा भी टूट गई जिससे पानी का प्रवाह और तेज हो गया।

बाढ़ नियंत्रण विभाग और एमसीडी की टीमें मौके पर मौजूद हैं और हालात पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना का बढ़ता जलस्तर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए मुसीबत बन गया है। घरों में पानी भरने से लोगों को सिग्नेचर ब्रिज के पास शरण लेनी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि शासन-प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली और न ही टेंट या अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई।

नागपुर: फैक्ट्री में धमाका, एक की मौत

नागपुर

महाराष्ट्र के नागपुर जिले में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात एक विस्फोटक फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि जिले के बाजारगांव स्थित सोलर एक्सप्लोसिव्स की आरडीएक्स यूनिट में रात करीब 12:30 बजे विस्फोट हुआ। पुलिस के अनुसार, 25 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एनसीपी (शरद पवार) नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की।

'आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहे'

समुद्री क्षेत्र में हरित ईंधन आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल बंदरगाह निकासी को बढ़ावा मिलेगा

- आतंकवाद को लेकर हमारी चिंताएं समान हैं। वे एकजुटता से आतंकवाद का मुकाबला करें

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिंगापुर के अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद साझा प्रेस वार्ता की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, 'आतंकवाद को लेकर हमारी चिंताएं समान हैं। हमारा मानना है कि सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है कि वे एकजुटता से आतंकवाद का मुकाबला करें। मैं पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति व्यक्त की गई संवेदनाओं और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में उनके समर्थन के लिए प्रधानमंत्री वांग और सिंगापुर सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हुए समझौते से समुद्री क्षेत्र में हरित ईंधन आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल बंदरगाह निकासी को बढ़ावा मिलेगा। भारत अपने बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास पर तेजी से काम कर रहा है। इसमें सिंगापुर का अनुभव बेहद उपयोगी है।

ई-वेस्ट से निकाले जाएंगे कीमती खनिज, मंजूरी

- बैटरी अपशिष्ट और ई-कचरे को रिसायकल करने की क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करता है

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगाई है। जिसमें मंत्रिमंडल ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों के रिसायक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।

70 हजार नौकरियां सृजित होने की उम्मीद

यह महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के लिए बैटरी अपशिष्ट और ई-कचरे को रिसायकल करने की क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करता है। यह योजना नई इकाइयों में निवेश के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधीकरण पर भी लागू होगी। प्रति इकाई कुल प्रोत्साहन (कैपेक्स प्लस ओपेक्स सब्सिडी) बड़ी इकाइयों के लिए 50 करोड़ रुपये और छोटी इकाइयों के लिए 25 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के अधीन होगा। इस योजना से लगभग 8,000 करोड़ रुपये का निवेश आने तथा लगभग 70,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है।

क्या है योजना का मकसद?

यह योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (एनसीएमएम) का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत में ऐसे खनिजों की घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और अन्य हाई-टेक उद्योगों में होता है। खनिजों की खदानें तैयार होने और उत्पादन शुरू करने में कई साल लगते हैं। ऐसे में ई-वेस्ट और बैटरी कचरे की रीसाइक्लिंग के जरिए हासिल करना व्यावहारिक तरीका है।

पेड़ों की अवैध कटाई के कारण आपदा आई: सुप्रीम कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया

नई दिल्ली

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है।

कोर्ट ने आपदाओं का संज्ञान लेकर इन मामलों में केंद्र सरकार, एनडीएमए और चार राज्यों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दो हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में पेड़ों की अवैध कटाई के कारण आपदाएं आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की और सॉलिसिटर जनरल से सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने को कहा है।

किसे जारी किया गया नोटिस?

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और पंजाब की सरकारों को भी नोटिस जारी किए है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी है। मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ी बहकर आई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। इसलिए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाता है।

'पीएम की मां के लिए अभद्र भाषा' पर कर्ण सिंह आहत

नई दिल्ली

बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को खुद पीएम मोदी ने भी इस पर पहली बार प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मंच से बोली गई आपत्तिजनक भाषा को बिहार समेत पूरे देश की महिलाओं का अपमान करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मां का राजनीतिक सरोकार नहीं होने के बावजूद उन्हें गालियां दी गईं। जनता ऐसे व्यवहार को माफ नहीं करेगी। भाजपा आलाकमान समेत राज्य के नेता भी इस घटनाक्रम के खिलाफ आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण में वयोवृद्ध राजनेता कर्ण सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी की मां के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

मोदी के कूटनीतिक दांव से बढ़ी ग्लोबल साउथ की धमक

- भारत की रणनीतिक पैतरेबाजी से खुद अमेरिका हैरान है।
- ट्रंप के सहयोगियों के सुर बदले

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एससीओ सम्मेलन में जाना एक बड़ा कूटनीतिक दांव था। पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की एक फ्रेम में तस्वीरें देख कर पश्चिमी दुनिया बेचैन है। अमेरिका और यूरोप के विशेषज्ञ और नेता इस अप्रत्याशित स्थिति के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। ट्रंप टैरिफ के जवाब में भारत की रणनीतिक पैतरेबाजी से खुद अमेरिका हैरान है। भारत को लेकर आग उगल रहे ट्रंप और उनके सहयोगियों के सुर बदले हुए दिख रहे हैं। भारत, रूस और चीन की जुगलबंदी वैकल्पिक वर्ल्ड आर्डर का संकेत दे रही है।

चीन और भारत ने समझी व्यावहारिक जरूरत

चीन और भारत के संबंध दशकों से जटिल रहे हैं। इसका कारण दोनों देशों के बीच करीब चार हजार किलोमीटर सीमा का लेकर विवाद है। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद यह संबंध बेहद खराब हो गए थे। हालांकि 2023 के बाद संबंधों में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन ट्रंप 2.0 की नीतियों ने दोनों देशों को अहसास कराया कि बदली हुई परिस्थितियों में मतभेदों के बावजूद आर्थिक और दूसरे आपसी हितों के मुद्दों पर मिल कर काम करने की जरूरत है।

दुनिया में हर सात में एक व्यक्ति मानसिक बीमारियों से जूझ रहा

नई दिल्ली

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी नई रिपोर्ट में खुलासा किया है कि वर्ष 2021 में दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मानसिक बीमारियों से जूझ रहा था। आंकड़ों के अनुसार, दुनिया की सात में से एक आबादी यानी एक अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से प्रभावित थे। इनमें से दो-तिहाई मामले चिंता व अवसाद के थे। रिपोर्ट 'वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे' और 'मेंटल हेल्थ एटलस 2024' के अनुसार, मानसिक बीमारियों के कारण युवाओं पर गंभीर असर पड़ा है। आत्महत्या युवाओं में मौत का एक प्रमुख कारण है और यह विश्व स्तर पर हर 100 मौतों में से एक से अधिक के लिए जिम्मेदार है।

जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अब नहीं लगेगा जीएसटी

- सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में ऐलान किया

नई दिल्ली

जीएसटी परिषद ने पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत दी है। अब व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे। दरअसल, इन बीमा उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट दे दी गई है। संशोधित दरें 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में ऐलान किया कि सभी तरह की व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इनमें टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी शामिल हैं। फिलहाल इन पर अभी 18 फीसदी जीएसटी लगता है।

पुनर्बीमा भी अब शून्य जीएसटी श्रेणी में

जीएसटी परिषद के फैसले के बाद अब इनपर पूरी तरह से छूट दी जाएगी। इस बदलाव के साथ सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियां- जिनमें टर्म लाइफ, यूलिप और एंडोमेंट प्लान शामिल हैं और साथ ही उनका पुनर्बीमा भी अब शून्य जीएसटी श्रेणी में आ जाएगा।

उपराष्ट्रपति चुनाव: लोकतंत्र को खतरा नहीं: बी सुदर्शन रेड्डी

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। रेड्डी का मानना है कि यह उम्मीदवारी उनकी संविधान यात्रा का ही विस्तार है और यह यात्रा चुनाव नतीजों के बाद भी जारी रहेगी, भले ही उनकी जीत हो या हार। भारत के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं, स्याह बादल हैं, पर छंट जाएंगे। मैं भारत के संविधान को मानने वाला हूं और 51-52 साल से संविधान से जुड़ा हूं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना उसी सांविधानिक परंपरा का हिस्सा है। इसमें सियासी दखल नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सांविधानिक पीठ पर बैठते हैं।

जोरदार बारिश व बादल फटने की घटनाओं के चलते भाखड़ा बांध के पीछे बनी विशाल गोबिंद सागर झील का 1678.10 फीट पंहुच गया

पंजाब: बाढ़ से 1400 गांव और 4.5 लाख लोग प्रभावित... 37 की मौत

- सभी विभागों को प्रभावित सेवाओं को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के आदेश दिए

चंडीगढ़

हिमाचल और पंजाब में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात खराब हो गए हैं। पंजाब के सभी 23 जिलों में 1400 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है।

सभी विभागों को प्रभावित सेवाओं को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के आदेश दिए गए हैं। सभी विभागों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और विभागों को राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा है। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सभी सरकारी, एडेड, मान्यता प्राप्त, निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थानों को 7 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है। पहले इन्हें 3 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया था।

अब तक 37 लोगों की जान गई

राज्य में 3.5 लाख एकड़ जमीन में फसल डूब गई है। अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार को भी तीन लोगों की मौत हो गई। इनमें बरनाला में बुजुर्ग दंपती और लुधियाना में एक युवक शामिल हैं। राज्य में 4.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही जोरदार बारिश व बादल फटने की घटनाओं के चलते भाखड़ा बांध के पीछे बनी विशाल गोबिंद सागर झील का 1678.10 फीट पंहुच गया है जो खतरे के निशान से मात्र दो फीट कम है। खतरे का निशान 1680 फीट है। भाखड़ा से रोज 75 हजार क्यूसेक पानी टर्बाइनों व फ्लड गेटों से छोड़ा जा रहा है। नंगल हाइडल नहर और श्री आंनदपुर साहिब हाइडल नहर में 9 हजार जबकि सतलुज दरिया में लगभग 57 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

पौंग बांध खतरे के निशान से चार फीट ऊपर

होशियारपुर के तलवाड़ा मेंपौंग बांध जलाशय में जलस्तर खतरे के निशान से चार फीट ऊपर चला गया है। इसलिए बीबीएमबी ने धीरे-धीरे पानी की मात्रा बढ़ाकर एक लाख क्यूसेक करने का निर्णय लिया है।

देवगौड़ा पीएम मोदी की नीति की जमकर की सराहना

- मीडिया में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए

बंगलूरू

पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और उनकी 'मल्टी-अलाइनमेंट'रणनीति की खुलकर सराहना की है। अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ को अनुचित और अन्यायपूर्ण टैरिफ करार देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की दूरदृष्टि और सक्रिय कूटनीति से आने वाले समय में भारत को बड़े लाभ होंगे। एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि अमेरिका की यह टैरिफ पॉलिसी जल्द ही 'धर्म और न्याय' के दबाव में बदलने को मजबूर होगी क्योंकि भारत के पास दुनिया में सबसे अनोखा आर्थिक, जनसांख्यिकीय और लोकतांत्रिक संतुलन है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत अपने सभ्यता मूल्यों के साथ दुनिया में नई पहचान बनाएगा।

रूस-चीन दौरे पर मिली सफलता

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने पीएम मोदी के हालिया जापान और चीन दौरेकी भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'मुझे राहत है कि आपने अमेरिका के अनुचित टैरिफ वार के बाद विकल्प तलाशने की दिशा में सक्रिय प्रयास किए हैं। मुझे भरोसा है कि इन दौरों और आपकी बातचीत का भारत को बड़ा फायदा मिलेगा।' उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, वे सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक नए विश्व क्रम की शुरूआत का संकेत देते हैं, जिसमें भारत केंद्र में होगा।

हरियाणा में बर्बादी की बारिश: अंबाला-भूना में घरों में घुसा पानी

3 ड्रेनों में आई दरार; लाडवा में तटबंध टूटा, ड्रेन टूटने से करीब 300 एकड़ में

करनाल/हिसार/रोहतक/ फरीदाबाद

बारिश रूपी आफत का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। हरियाणा में नदी-नालों में उफान आने से स्थिति चिंताजनक हो गई है। हिसार, सिरसा और झज्जर में ड्रेनों में दरार आ गई है। घरों स्कूलों, अस्पतालों में पानी भर गया है। खेतों में फसलें डूब चुकी हैं। बारिश जनित हादसों में चार जिलों 30 मकान ढह गए या क्षतिग्रस्त हुए और आठ लोगों की जान चली गई। 9 जिलों के प्रभावित इलाकों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गईं। पांच जिलों में करीब 200 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। सात जिलों की 1,71,665 एकड़ फसल डूबी हुई है।

ड्रेन टूटने से करीब 300 एकड़ में फसलें डूबीं

फतेहाबाद के भूना में बाढ़ जैसे हालात हैं। 73 गांवों में जलभराव है। 600 घरों में पानी घुसने से लोग बेहाल हैं। करीब 80 परिवारों ने पलायन कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। हिसार में गांव घिराय व कैमरी के पास घग्गर ड्रेन टूटने से करीब 300 एकड़ में फसलें डूब गईं। बहादुरगढ़ में दिल्ली सीमा पर मुंगेशपुर ड्रेन 50 फीट तक टूट गई जिससे पानी झाड़ौदा कलां के पास बसी गीतांजलि एन्क्लेव कॉलोनी में घुस गया। कुछ घरों में पानी भर गया। भिवानी जिले में करीब 4700 एकड़ फसल में जलभराव है। कई गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी स्कूलों में भी पानी भरा है।

फरीदाबाद के गांवों में पांच फीट तक भरा पानी

सिरसा में ओटू हेड में सुबह 21 हजार क्यूसेक जलस्तर था। वहीं, दोपहर बाद 18600 क्यूसेक रह गया। नेजाडेला गांव में करीब 25 परिवार के लोगों ने अन्यत्र स्थान पर शरण ली है। जलभराव से 5000 एकड़ फसल प्रभावित है। कृषि विभाग व राजस्व विभाग की टीमें आंकलन करने में जुटी हुई है। फतेहाबाद में घग्गर में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार सुबह 14,200 क्यूसेक था और शाम को 14,300 क्यूसेक हो गया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बसंतपुर व आस-पास के गांव में बुधवार को 5 फीट तक पानी भर गया है। ताजेवाला बैराज से देर बुधवार पूरे दिन छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का बहाव तेज हुआ है। जिले के 27 गांव प्रभावित हैं जिनमें 14 गांवों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। कई गांवों में लोगों के घर पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। राजपुर गांव के राहत केंद्र में सुबह तक 39 लोगों ने शरण ली। दुलेहपुर गांव में विस्थापित लोगों के लिए टीन शेड के नीचे अस्थायी इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ की 9 सदस्यीय टीम, एनडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड नावों के सहारे गांवों से लोगों को निकाल रहे हैं।

41 गांव प्रभावित

सोनीपत में यमुना नदी का पानी खेतों में घुस गया है। कई घर पानी से घिर गए। गन्नौर में तेज आंधी से 130 खंभे व 38 ट्रांसफॉर्मर गिर गए। रोहतक में 30 हजार एकड़ से अधिक फसलें बारिश के पानी में डूबी हैं। 41 गांव प्रभावित हो चुके हैं। सिरसा के चौपटा में हिसार घग्घर ड्रेन में गांव गुडिया खेड़ा के पास बुधवार को दरार आ गई। हालांकि ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए लीकेज को काबू कर लिया। कैथल जिले के छह गांवों में नदी का पानी आया है।

करीब 400 एकड़ फसल डूबी

पानी के कारण करीब 400 एकड़ फसल डूबने का अनुमान है। कुरुक्षेत्र रात के समय ईस्माइलाबाद में मारकंडा व लाडवा में राक्षी नदी का तीन स्थानों पर तटबंध टूटने से लाडवा शहर और नजदीकी गावों में पानी भर गया है। प्रभावित गांवों में एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। 35 बच्चों व करीब 200 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। करनाल के कुंजपुरा, घरौंडा और इंद्री के करीब 34 गांव के खेतों में यमुना का पानी घुस चुका है।

झज्जर में तीन हजार एकड़ फसलें डूबी, नौ गांवों में जलभराव

ड्रेन नंबर-आठ में पानी का बहाव ज्यादा है। बारिश के चलते बेरी, साल्हावास और झज्जर में तीन हजार एकड़ में फसलें डूबी हैं। माजरा बी, माजरा डी, मलिकपुर समेत नौ गांवों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। भंभेवा, दूबलधन बिध्याण, किरमाण, जहाजगढ़ के सरकारी स्कूलों में पानी भरा हुआ है।

हिसार के 30 गांवों-ढाणियों में भरा पानी

जिले में करीब 60 हजार एकड़ फसलें जलमग्न हैं। 30 गांवों के बाहरी बस्तियों और ढाणियों में पानी भरा हुआ है। 36 स्कूलों के परिसर में जलभराव है। मिजार्पुर में करीब 20 मकान मालिकों को जलभराव के कारण मकान खाली करने पड़े हैं। फतेहाबाद और सिरसा में घग्गर नदी में उफान के बावजूद अभी जलस्तर अभी खतरे के निशान के नीचे है।

कुल्लू: लैंडस्लाइड से मलबे में दबे सात लोग

कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के अखाड़ा बाजार में वीरवार सुबह करीब छह बजे दो मकान के ऊपर भूस्खलन हुआ है। मकान के अंदर सात से आठ लोग दब गए हैं। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान जारी किया। एक शव बरामद कर लिया है। शव की पहचान महराज निवासी कंगन श्रीनगर के रूप में हुई है। जबकि सात लगते धर से तीन घायलों को रेस्क्यू कर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू भेज गया है। मौके पर कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी पहुंच चुके हैं। अन्य लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। अभी मकान में छह लोग दबे हुए हैं। संख्या और ज्यादा हो सकती है। साथ में रह रहे अब्दुल ने बताया कि तीन कमरों में सात लोग रह रहे थे। इसमें एक व्यक्ति ने कूदकर जान बचाई। एक का शव बरामद हो चुका है जबकि पांच लोग अभी भी दबे हुए हैं। जिनका रेस्क्यू चल रहा है। यह सभी लोग जम्मू-कश्मीर के बताए जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण रेस्क्यू करने में दिक्कत पेश आ रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मौके पर उपायुक्त कुल्लू तोरूल एस रवीश, एसडीएम कुल्लू निशातं ठाकुर घटना स्थल पर पहुंचे। यह हादसा सुबह करीब छह बजे के करीब पेश आया है। बशीर अहमद बानी ने बताया कि मकान में जो लोग रह रहे थे। यह सभी शुक्रवार को नमाज पढ़ने के यह सभी लोग यहां पर रुके हुए थे। सभी जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं। एक स्थानीय महिला भी इसमें दबी हुई है। सनद रहे कि पिछले कल इनपर अखाड़ा में मकान के ऊपर भूस्खलन होने से उसमे दो लोग मलबे में दब गए हैं। इसमें दो शव बरामद किए गए हैं। यहां पर भी कुछ लोग दबे हुए हैं।

'व्हिसलब्लोअर' को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना पड़ा महंगा,

नई दिल्ली

देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' के सहायक कमांडेंट राहुल सोलंकी 'व्हिसलब्लोअर' को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना महंगा पड़ रहा है। सोलंकी ने भ्रष्टाचार के मामले न केवल डीजी के समक्ष उठाए हैं, बल्कि वे दिल्ली हाईकोर्ट के संज्ञान में भी आ चुके हैं। सहायक कमांडेंट राहुल को पहले नोएडा से सोनीपत ग्रुप सेंटर पर अटैच कर दिया गया। इसके बाद सहायक कमांडेंट का तबादला, मणिपुर की 87वीं बटालियन में किए जाने का आदेश जारी हुआ।

उत्तराखंड: रोपवे परियोजना की दिशा में पहल, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

देहरादून

उत्तराखंड में देश की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष एस नरिंदर जीत सिंह बिंद्रा के नेतृत्व में विभिन्न सिख संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंटकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक प्रस्तावित 12.4 किमी लंबी इस रोपवे परियोजना की अनुमानित लागत 2,730.13 करोड़ है। बिंद्रा ने कहा कि हेमकुंड साहिब सिख धर्म का पवित्र तीर्थ है, जहां तक पहुंचना बेहद कठिन और जोखिमभरा होता है। इस रोपवे से न केवल लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा सरल और सुरक्षित होगी बल्कि स्थानीय व्यक्तियों के लिए भी यह आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का मार्ग खोलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। यह परियोजना श्रद्धा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक होगी तथा निर्माण कार्य में पर्यावरणीय मानकों और जनभावनाओं का ध्यान रखा जाएगा।

पुलिस थानों में सीसीटीवी की कमी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संज्ञान लिया

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार इस साल राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 मौतें हुईं, शब्बीर अहमद की याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार इस साल राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 मौतें हुईं। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की उस याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा। याचिका में उन्होंने आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी है। हालांकि, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पहले जानते हैं कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की याचिका के बारे में

शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता बहुत बीमार है। पीठ ने उच्च न्यायालय के इस साल 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली शाह की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया।

प्राइवेट कर्मचारियों को अब 9 की जगह करना होगा 10 घंटे काम

मुंबई

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बुधवार को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम कार्य अवधि को बढ़ा दिया है। सरकार ने इस संबंध में नौ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के बयान के अनुसार, कानून में परिवर्तन का मुख्य कारण निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। बता दें कि राज्य सरकार के फैसले के बाद प्राइवेट कंपनियों के काम करने वालों को 9 की जगह 10 घंटे काम करना होगा।

फडणवीस सरकार ने दी बदलावों की मंजूरी

महाराष्ट्र में सूबे के सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कार्यबल द्वारा सुझाए गए बदलावों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि महाराष्ट्र अब तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में शामिल हो गया है, जहां पहले ही ऐसे सुधार किए जा चुके हैं।

अब से क्या-क्या बदल जाएगा?

राज्य सरकार द्वारा जारी बयान में बताया गया कि ये संशोधन, फैक्ट्री अधिनियम, 1948 और महाराष्ट्र दुकान एवं स्थापना (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 2017 में किए जाएंगे। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के बदलाव के बाद उद्योगों में प्रतिदिन काम के घंटो की सीमा 9 से बढ़ाकर 12 घंटे की जाएगी। इसके अलावा आराम करने का समय पांच घंटे की बजाय अब छह घंटे के बाद मिल सकेगा। वहीं, कानूनी ओवरटाइम की सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर प्रति तिमाही 144 घंटे की जाएगी। हालांकि, इसके लिए श्रमिकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। कानून के लागू होने के बाद काम के घंटों को बढ़ा कर साढ़े 10 से 12 घंटे कर दिया जाएगा।

9 घंटे के जगह 10 घंटे करना होगा काम

ठीक ऐसे ही संशोधित दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत प्रतिदिन काम के घंटों को बढ़ा कर 9 से 10 घंटे कर दिया गया है। वहीं, ओवरटाइम की सीमा को 125 से बढ़ाकर 144 घंटे और आपातकालीन ड्यूटी घंटों को 12 घंटे कर दिया जाएगा। बता दें कि ये बदलाव 20 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे।

अब चेक बाउंस होने पर नहीं जाना पड़ेगा जेल...

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद शिकायतकर्ता के साथ समझौता कर लेता है, तो वह जेल की सजा से बच सकता है। कोर्ट ने अहम फैसले में कहा, एक बार पार्टियों के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस का अपराध मुख्य रूप से दिवानी प्रकृति का है और इसे विशेष रूप से आपराधिक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक निजी विवाद है, जिसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आपराधिक क्षेत्र में लाया गया है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला पलटा

यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस निर्णय को पलटता है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बावजूद चेक बाउंस मामले में सजा को रद्द करने से इन्कार किया गया था। जब दोनों पक्षकार समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं और शिकायतकर्ता डिफॉल्ट राशि का पूर्ण और अंतिम निपटारा स्वीकार कर लेता है, तो धारा 138 के तहत कार्यवाही को बरकरार नहीं रखा जा सकता। खंडपीठ ने फैसले में कहा- पक्षकार समझौता इसलिए करते हैं ताकि वे मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से बच सकें। अदालतें इस तरह के समझौते को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं।

फर्जी एग्रीमेंट/किसान क्रेडिट कार्ड से लिया ऋण, दूसरे काम में लगाया पैसा

नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मछली टैंक ऋण लेकर केनरा बैंक, कंचारपालेम शाखा, विशाखापत्तनम से धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 2.20 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति और 1.36 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्ति (कुल 2.22 करोड़ रुपये) अनंतिम रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियां डोडला वेंकट कृष्ण कुमार और उनकी पत्नी डोडला सुनीता के नाम पर आवासीय फ्लैट, भूखंडों व बैंक बैलेंस के रूप में हैं। उन्होंने केसीसी मछली टैंक ऋण राशि से ये संपत्तियां जुटाई थी। यह लोन देवसनी निर्मला, अदारी चंद्रकला और कोव्वुरी श्रीनिवास ने केनरा बैंक, कंचारपालेम शाखा, विशाखापत्तनम से लिया गया था।

कपास पर आयात शुल्क रद्द करने वाली अधिसूचना वापस लेने की मांग

एसकेएम ने पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र

नई दिल्ली

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कपास किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें मांग की है कि हाल ही में जारी वह अधिसूचना तुरंत और बिना शर्त वापस ली जाए, जिसमें कपास पर 11 फीसदी आयात शुल्क खत्म कर दिया गया है। एसकेएम ने यह भी मांग की कि 50 फीसदी तक का आयात शुल्क फिर से लगाया जाए। खुले पत्र में कहा गया है, 'हम, कपास उत्पादक और इस महान राष्ट्र के धन सृजन में योगदान देने वाले किसान, आपके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे व्यवस्थित विश्वासघात पर अपना गहरा आक्रोश व्यक्त करते हैं।' किसानों ने कहा कि कपास की कीमतें पहले से ही गिर रही हैं और किसान भारी कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। आयात शुल्क समाप्त होने से घरेलू बाजार में कीमत और गिरेगी। साथ ही किसानों की हालत और खराब होगी।

60 लाख किसान परिवारों की आजीविका पर संकट

पत्र में आगे कहा गया है कि आयात शुल्क समाप्त होने से देशभर के करीब 60 लाख कपास उत्पादक किसान परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। एसकेएम ने दावा किया कि किसानों की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पत्र में कहा गया, 'साल 2025 के पहले तीन महीनों में ही अकेले महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में 767 किसानों ने आत्महत्या की है।'

4.5 लाख से ज्यादा किसान कर चुके आत्महत्या

किसानों ने बताया कि उत्पादन लागत बढ़ने और फसल का उचित दाम न मिलने की वजह से ये 'मानव-निर्मित त्रासदियां' हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 4.5 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पत्र में यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को केवल एक लाख रुपये की मदद देती है। एसकेएम ने मांग की कि यह मुआवजा राशि तुरंत बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाए और यह प्रावधान 2014 से लागू किया जाए।

पिछले 10 वर्षों में सीसीआई-नेफेड के जरिये खरीदी गई केवल 13 फीसदी कपास

किसान संगठन ने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में औसतन केवल 13 फीसदी कपास ही भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और नाफेड के जरिये खरीदी गई, जबकि 87 फीसदी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम दाम पर बेचने को मजबूर रहे। एसकेएम का कहना है कि सी2+50 फीसदी फामूर्ले के हिसाब से कपास का समर्थन मूल्य 10,075 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। मौजूदा हालात में किसानों को करीब 2,365 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है।

भारत में बनेगी सिक्योर चिप; एलएंडटी, आईआईटी गांधीनगर और सी-डैक के बीच हुआ समझौता

नई दिल्ली

भारत ने डिजिटल सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सेमीकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में एलएंडटी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज, आईआईटी गांधीनगर और सी-डैक ने मिलकर एक समझौता किया है। इस सहयोग का मकसद भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी सुरक्षित चिप बनाना है। इस चिप का पहला इस्तेमाल भारत के नए इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट में किया जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य में आपका पासपोर्ट और भी सुरक्षित और भरोसेमंद होगा। विदेश यात्रा करते समय नकली पासपोर्ट या डेटा चोरी जैसे खतरे और कम हो जाएंगे। अभी तक ऐसी ज्यादातर चिप्स विदेशों से आती थीं। इससे सुरक्षा पर सवाल उठते थे और भारत तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। अब जब सभी डिजाइन और बौद्धिक संपदा (आईपी) भारत में ही रहेंगे, तो देश की तकनीकी संप्रभुता भी मजबूत होगी। इस परियोजना में उद्योग, विश्वविद्यालय और सरकारी शोध संस्थान-तीनों मिलकर काम कर रहे हैं विशेषज्ञों का कहना है कि इससे युवाओं को सेमीकंडक्टर और डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में नए शोध और रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' योजना की दिशा में अहम कदम है।

न टेंट लगे और न ही शौचालय की सुविधा, पानी के लिए भी तरस रहे हैं लोग

दिल्ली के इस इलाके में पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं, पूर्वी दिल्ली में बाढ़ से राहत शिविरों में कमी, बुनियादी सुविधाओं के अभाव से लोग परेशान, विधायक और पार्षद ने नाव से लोगों को बचाया

नई दिल्ली
दिल्ली में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। जलस्तर से प्रभावित हुए लोगों के लिए टेंट कम पड़ गए हैं।
शौचालय व पीने के पानी तक के लिए लोग परेशान हैं। सरकारी सुविधाएं न मिलने पर लोग फ्लाईओवर के नीचे, फुटपाट व डिवाइडर व बस स्टैंड पर रहने को मजबूर हैं। वहीं, बारिश ने उनकी मुसीबत बढ़ा रखी है। तिरपाल ओढ़कर लोग खुद व अपने बच्चों और सामान को वर्षा से बचा रहे हैं।
मयूर विहार फेज-एक में लगे राहत शिविर में यमुना का पानी पहुंच गया है। यहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह पहुंचाया गया है।
पुराना लोहापुल, उस्मानपुर पुश्ता, सिग्नेचर ब्रिज समेत कई स्थानों प्रभावित लोग रहे रहे हैं।
आरोप है कि प्रशासन की ओर से कुछ ही टेंट लगाए गए हैं। जब जल स्तर बढ़ गया तक टेंट की कुछ ही संख्या बढ़ाई है। उन टेंट में लाइट भी नहीं है। वर्षा व धूप का सितम वह झेल रहे हैं। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वह टेंट लगाए।

बाढ़ के पानी से दिल्ली बेहाल... न रिंग रोड बचा, न सीएम दफ्तर और न यमुना के घाट

विधायक व पार्षद नाव लेकर लोगों को बचाने पहुंचे
घोंडा के विधायक अजय महावर व भजनपुरा की पार्षद रेखा रानी बोट लेकर गढ़ी मांडू गांव गए। उन्होंने कई लोगों को बोट से रेस्क्यू किया। वर्षा के बीच भी रेस्क्यू जारी रखा।
विधायक ने उस्मानपुर गांव की चौपाल प्रभावित लोगों के लिए खोल दी है, लोग वहां रह सकते हैं।

कुत्तों को बचाने पहुंच रही हैं संस्थाएं
यमुना खादर में पानी में फंसे कुत्तों को बचाने के लिए कई संस्थाएं आगे आई हैं। मयूर विहार, गीता कालोनी, पुराना लोहापुल व सोनिया विहार, पुराना उस्मानपुर में संस्थाएं पहुंच रही हैं। बोट के जरिये वह पानी में कुत्तों को तलाश रही हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही हैं।

यमुना के बढ़ते जलस्तर से राजधानी में हालात खराब

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में यमुना नदी के उफान से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थिति यह है कि यमुना का पानी सिविल लाइंस और दिल्ली सचिवालय के पास तक पहुंच चुका है। बाढ़ की चेतावनी के बीच गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को लगातार चौथे दिन भी बारिश का दौर जारी है। वहीं, यमुना नदी का पानी रिंग रोड सिविल लाइंस क्षेत्र की सर्विस लेन में भरा गया है। इससे रिंग रोड पर कश्मीरी गेट के पास सड़क के दोनों तरफ

वाहनों की रफ्तार थम गई है और लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली में पुराना लोहा पुल बंद होने से 40 ट्रेनें निरस्त की गई हैं। रिंग रोड पर बेला रोड सिविल लाइन के पास जमा हुआ पानी। फिलहाल यातायात चल रहा है। इस बीच, राहत भरी खबर यह है कि पूर्वी दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटने लगा है। बृहस्पतिवार सुबह यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर दर्ज किया गया है।

सिविल लाइन और कश्मीरी गेट में बाढ़ जैसे हालात

नई दिल्ली
देश की राजधानी दिल्ली के वीआईपी क्षेत्रों में से एक है सिविल लाइन। मगर बरसात और बाढ़ की तैयारियों में यह स्थान भी पिछड़ा हुआ है। गुरुवार को सिविल लाइन क्षेत्र में यमुना के पानी से हुआ जलभराव बहुतों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। हालात बिगड़ते देख एनडीआरएफ के जवानों को नाव के जरिये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालना पड़ा। यमुना का पानी और बीते कुछ समय हो रही मूसलाधार बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया है। जगह पानी भर आने से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। वह भी तब सिविल लाइन क्षेत्र में ही दिल्ली की मुख्यमंत्री और एलजी का भी आवास है। ऐसे में जनता की दिक्कतों का समय रहते समाधान करने में भी संबंधित विभाग पीछे रह गये। यह तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं।

बाढ़ जैसे हालातों में एक बड़ी समस्या आ जाती है गाड़ियों के रखरखाव की। अब जैसे इस तस्वीर में ही दिख रहा है कि किस तरह से जलभराव में फंसी गाड़ी पानी से पूरी तरह से सराबोर हो चुकी है। इस जलभराव से गाड़ी को बाहर निकालने में लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इन हालातों में गाड़ी मालिकों के लिये अपनी महंगी सम्पत्ति को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। गाड़ी में पानी चले जाने से कई बार उसके महंगे पार्ट्स खराब हो जाते हैं। इससे गाड़ी मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ आ जाता है। नालियों की समय पर सफाई न होने से ऐसी समस्या से सिर्फ आम लोगों को ही जूझना पड़ता है। यह तस्वीर भी सिविल लाइन क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित स्थान की है।

लोहापुल के पास प्रशासन की बहुत बद इंतजामिया हैं। एक ही शौचालय है, वह बहुत गंदा है। खुले में लोग शौच कर रहे हैं। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है।
- बीएन मिश्रा, पुराना लोहापुल

प्रशासन ने नाम मात्र शिविर उस्मानपुर पुश्ता रोड पर बनाएं हैं। मैं अपने परिवार के साथ बस स्टैंड पर रह रही हूं। वर्षा में भीगने से परिवार के कई लोग बीमार हो गए। खाना भी नहीं मिल रहा है।
- बिलकिस

कश्मीरी गेट पर भी जलभराव

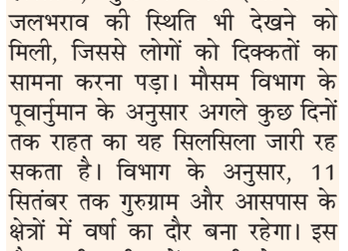

वहीं, कश्मीरी गेट क्षेत्र का भी हाल बहुत बुरा है। ऐसा लग रहा है जैसे यमुना के पानी ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है। एएनआई ने ड्रोन वीडियो के माध्यम से इस समस्या को दिखाया है। कश्मीरी गेट के बस स्टैंड के चारों ओर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, करनाल, नूंह, पलवल, पानीपत, सोनीपत में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।
कब तक जारी रहेगा बारिश का दौर?
इससे पहले, गुरुग्राम में हुई वर्षा से शहर का मौसम बदल गया। दिनभर आसमान घने बादलों से ढका रहा और उद्योग विहार, शंकर चौक व एंबियंस मॉल क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। वहीं मानेसर इलाके में भी बूंदाबांदी के चलते लोगों ने राहत महसूस की। मौसम बदलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रहा। दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहे और बीच-बीच में हल्की ठंडी हवा भी चलीं। शाम के समय हुई वर्षा के बाद शहर के कई हिस्सों में मौसम सुहाना हो गया। हालांकि, कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के पूवार्नुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राहत का यह सिलसिला जारी रह सकता है। विभाग के अनुसार, 11 सितंबर तक गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का दौर बना रहेगा। इस दौरान बीच-बीच में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में और गिरावट आ

जीटी करनाल फ्लाईओवर का हिस्सा धंसा, गड्ढे में फंसकर ऑटो ड्राइवर घायल

● इस दुर्घटना में चालक चोटिल हो गया। चालक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है

नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (जीटी करनाल रोड) पर अलीपुर के पास बृहस्पतिवार सुबह फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया है। इस गड्ढे में एक ऑटो रिक्शा फंस गया और चालक घायल हो गया। पुलिस ने फिलहाल फ्लाईओवर पर वाहनों की

आवाजाही रोक दी है और यातायात को डायवर्ट कर सर्विस लेन से वाहनों को निकाला जा रहा है। यह वाक्या सुबह आठ बजे का बताया जा रहा है। फ्लाईओवर पर एकाएक रोड धंस गया और चार से पांच फीट गहरा गड्ढा बन गया है। गड्ढे के आसपास दरारें भी दिखाई दे रही हैं। इसी दौरान वहां से गुजर रहा ऑटो रिक्शा गड्ढे में फंस? गया।
इस दुर्घटना में चालक चोटिल हो गया। चालक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सीएम रेखा ने विकास भी, विरासत भी अभियान का किया शुभारंभ

● 15 शिक्षकों को शिक्षक सम्मान पुरस्कार से अलंकृत करना इस नई यात्रा का प्रेरक प्रारंभ है

नई दिल्ली
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को नई दिल्ली पालिका परिषद (एनडीएमसी) के विकास भी, विरासत भी अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) से प्रेरित विकास भी विरासत भी पहल बच्चों को आधुनिक क्षमताओं से

सशक्त करते हुए, हमारी संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ेगी। अटल आदर्श और नवयुग विद्यालयों के 15 शिक्षकों को शिक्षक सम्मान पुरस्कार से अलंकृत करना इस नई यात्रा का प्रेरक प्रारंभ है। जिस प्रकार आधुनिक विमान को दिशा पायलट ही देता है, वैसे ही बच्चों को नई सोच और शिक्षा की उड़ान देने का दायित्व हमारे शिक्षकों पर है। उन्होंने कहा कि विकास भी, विरासत भी दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए शिक्षा का आदर्श मॉडल बनेगा, यह उनको विश्वास हैं। इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा एवं एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने एक्स पोस्ट में कहा कि आज एक गौरवपूर्ण और प्रेरणादायी क्षण का साक्षी बनने का अवसर मिला, जब नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विकास भी, विरासत भी की भावना को साकार करते हुए एक नई शैक्षिक पहल का शुभारंभ किया गया। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य बच्चों को आधुनिक क्षमताओं से सशक्त करते हुए उन्हें भारत की संस्कृति और परंपराओं से भी गहराई से जोड़ना है।

संघ: शताब्दी वर्ष की तैयारियों परिस्थितियों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुक्रवार से जोधपुर में आरंभ होगी। तीन दिनों (5, 6 और 7 सितंबर) तक चलने वाली इस बैठक में भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद, मजदूर एवं किसान संघ सहित संघ से जुड़े विविध संगठन भाग लेंगे। बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों और देश की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा होगी।

पंजाब बाढ़ में व्यस्त केजरीवाल और सिसोदिया कोर्ट में पेश नहीं हुए

नई दिल्ली
आबकारी घोटाला के मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुरुवार को अदालत में पेश नहीं हुए। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को करने का आदेश दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को छोड़कर

सभी आरोपित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। कोर्ट में पेशी से छूट की मांग करके केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से कहा गया कि दोनों पंजाब में आयी बाढ़ में राहत और बचाव कार्यों का समन्वय में व्यस्त हैं।

अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में शिखर धवन से पूछताछ करेगी

नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले की चल रही जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब कुछ दिन पहले ही ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से पूछताछ की थी। अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को एजेंसी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।

नगर निगम के एक्शन पर जमकर हंगामा, कर्मचारियों के साथ हुई हाथापाई

● रोहिणी नगर निगम जोन की ओर से मवेशी पकड़ने और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया

नई दिल्ली
बाहरी दिल्ली में रोहिणी नगर निगम जोन की ओर से मवेशी पकड़ने और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। दोनों ही अभियान के दौरान लोगों के विरोध के बाद हंगामा खड़ा हो गया। अवंतिका में

सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे मवेशी पकड़ने के लिए अभियान चलाया। बताया गया कि पहला मवेशी पकड़ने की कोशिश में ही दो लोगों ने गोवंशी को गाड़ी में बैठाने से रोका। इस क्रम में आरोपी ने निगम कर्मचारियों से हाथा-पाई की। मामला बढ़ता देख टीम ने पुलिस को बुलाया। निगम की शिकायत पर दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उधर, सुल्तानपुरी में फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के दौरान टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि एक निगम पार्षद ने कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया है। निगम उपायुक्त ने बताया कि पार्षद के खिलाफ शिकायत मिली है, अभी इसकी जांच की जा रही है। अवंतिका क्षेत्र में एक पूर्व निगम पार्षद की ओर से दर्ज कराई शिकायत के बाद नगर निगम की वेटनरी ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। नगर निगम टीम ने एक गोवंशी को गाड़ी में बैठाने लगे तो इसी दौरान युवकों ने गाय को छुड़वाने का प्रयास किया। दोनों को रोका तो कर्मचारियों से हाथापाई की।

सरकार 24 रुपये किलो बेचेगी प्याज, मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली
केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को यहां एनसीसीएफ, नैफेड और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की खुदरा बिक्री का शुभारंभ किया।
उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रह्लाद जोशी ने 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी वाले प्याज बेचने वाली वैन को

हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। फिलहाल नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में प्याज की खुदरा बिक्री आज से शुरू हो गई। इस कार्यक्रम के साथ ही सरकारी बफर स्टॉक से प्याज

● नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में प्याज की खुदरा बिक्री आज से शुरू हो गई

की लक्षित और संतुलित मात्रा में आपूर्ति शुरू हुई, ताकि उपभोक्ताओं को यह आवश्यक सब्जी किफायती दामों पर उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार किसानों और उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना भारत सरकार की प्राथमिकता है। मूल्य स्थिरीकरण उपायों के माध्यम से विभिन्न प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों ने हाल के महीनों में महंगाई दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जुलाई 2025 में सामान्य खुदरा महंगाई दर 1.55 फीसदी रही, जो लगभग आठ वर्षों में सबसे कम है। बफर स्टॉक से प्याज का संतुलित और लक्षित निपटान, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और स्थिर मूल्य व्यवस्था बनाए रखने के सरकार के प्रयासों का एक अभिन्न अंग है।

तीन लाशें मिलने से फैली सनसनी, पुलिस तीनों की नहीं कर सकी शिनाख्त

● दिल्ली में अज्ञात शव मिलने से सनसनी
● पुलिस ने शुरू की शवों की शिनाख्त

नई दिल्ली
नई दिल्ली में उत्तरी-पश्चिमी जिले में दो शख्स और रोहिणी जिला में एक महिला का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि तीनों मृतकों के पास शिनाख्ती कागजात नहीं मिले हैं, जिससे की उनकी

पहचान हो सके। वहीं, पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस शवों की शिनाख्त के लिए स्थानीय लोगों के अलावा अन्य पुलिस थानों से पता कर रही है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर शवों के मिलने के स्थान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। उत्तरी-पश्चिमी जिला के जहांगीरपुरी स्थित विक्रम बत्रा फ्लाइओवर चौक के पास दो सितंबर को 55 वर्षीय शख्स का शव संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि शव पर चोट के निशान नहीं है। मृतक के पास से कोई शिनाख्ती कागजात भी नहीं मिले।

संपादक की कलम से

भारत को एक राष्ट्र के रूप में जल सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी

डे जीरो–एक ऐसा शब्द है जो अब केवल एक संभावित आपदा नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक का प्रतीक बन चुका है। यह शब्द पहली बार 2018 में वैश्विक स्तर पर चर्चा में तब आया जब दक्षिण अफ्रीका का कैपटाउन शहर पानी की आपूर्ति पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। डे जीरो वह दिन होता है जब शहर के सभी नल बंद कर दिए जाते हैं, और नागरिकों को सार्वजनिक वितरण केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़े होकर सीमित मात्रा में पानी प्राप्त करना पड़ता है। कैपटाउन में यह सीमा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 25 लीटर निर्धारित की गई थी। हालांकि इस संकट का कारण केवल जलवायु परिवर्तन या वर्षा की अनिश्चितता नहीं था–यह दशकों की नीति विफलता, शहरों का अति-विस्तार, परंपरागत जल स्रोतों की उपेक्षा और जल प्रबंधन में बड़ी खामियों का संयुक्त परिणाम था।

कैपटाउन ने कड़ी नीतियों और नागरिक सहभागिता से इस आपदा को कुछ समय के लिए टाल दिया है। लेकिन पानी की गंभीर किल्लत की आहट अब भारत के दरवाजे तक होने लगी है। भारत जैसे देशों में, जहां जनसंख्या अत्यधिक है, शहरीकरण अनियंत्रित है, और भूजल दोहन पर कोई स्पष्ट नियंत्रण नहीं–डे जीरो अब भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि एक आसन्न यथार्थ है।

बेंगलुरु, जिसे कभी झीलों का शहर कहा जाता था, आज जल संकट के सबसे भीषण दौर से गुजर रहा है। यहां की अधिकांश झीलें अब या तो कचरा डंपिंग साइट बन चुकी हैं या अवैध निर्माण की भेंट चढ़ गईं। भूजल स्तर हर वर्ष 10-12 मीटर की दर से नीचे जा रहा है। बेंगलुरु में डे जीरो की आंशिक झलक तब देखने को मिली जब पूरे शहर में टैंकर के पानी पर निर्भरता बढ़ी।

चेन्नई भी 2019 में डे जीरो जैसे संकट का सामना कर चुका है जब उसके चारों जलाशय सूख गए थे। वहीं दिल्ली की स्थिति भी बेहतर नहीं–शहर की मुख्य जलधारा यमुना प्रदूषण और अतिक्रमण की शिकार है, जबकि भूजल स्तर अत्यधिक गंभीर श्रेणी में जा चुका है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के 21 बड़े शहरों में जलापूर्ति पूरी तरह समाप्त हो सकती है।

पानी के मामले में हरियाणा की स्थिति भी चिंताजनक है। धान,गन्ने जैसी अत्यधिक जल-खपत वाली फसलों का विस्तार, सिंचाई तकनीकों का अल्प उपयोग और नगण्य वर्षा जल संचयन ने भूजल अंधाधुंध तरीके से समाप्त कर दिया। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार हरियाणा के 85 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में भूजल स्तर खतरनाक स्तर पार कर चुका है।

भारत में जल संकट के लिए जिम्मेदार केवल वर्षा की अनियमितता नहीं है, बल्कि जल निकायों पर अतिक्रमण, नीति असंगति, शहरी अपशिष्ट का जल स्रोतों में मिलना और लोगों में जल बचत के प्रति उदासीनता जैसे कारक भी उतने ही उत्तरदायी हैं।

जल संकट से निपटने के लिए कई योजनाएं तो बनाई गईं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कागजी आंकड़ों तक ही सीमित रह गया। मसलन, जल जीवन मिशन को सिर्फ हर घर नल तक सीमित समझा गया, जबकि उसका मूल उद्देश्य स्थानीय जल स्रोतों का सशक्तीकरण और सामुदायिक सहभागिता के जरिए जल आत्मनिर्भरता था।

इस स्थिति से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। जल को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानकर नागरिक सहभागिता पर बल देना होगा। जल संरक्षण को जीवनशैली में लाना होगा झ जैसे कैपटाउन में लोगों ने बर्तनों में नहाने का पानी जमा कर पौधों को सींचा, हाथ धोते समय नल बंद करना सीखा और शौचालयों में रिसाइकल पानी का प्रयोग शुरू किया।

भारत में भी प्रत्येक इमारत में वर्षा जल संचयन अनिवार्य करना चाहिए, जिसे स्थानीय निकाय सख्ती से लागू करें। भूजल का मापन, नियमन और पुनर्भरण एक समर्पित मिशन के तहत चलाया जाए। जल जीवन मिशन को स्थानीय स्रोतों को पुनर्जीवित करने और जल संरक्षण पर केंद्रित करना होगा। शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट की जगह परकोलेशन पिट्स, बायोस्वेल्स और हरित क्षेत्र बढ़ाने होंगे ताकि वर्षा जल भूमि में जज्ब हो सके। पानी की कीमत समझना और उपभोग पर नियंत्रण लाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए स्लैब आधारित मूल्य निर्धारण, जहां न्यूनतम जरूरतों के बाद अतिरिक्त खपत पर उच्च शुल्क लगे, एक व्यावहारिक नीति हो सकती है। इससे पानी का विवेकपूर्ण उपयोग प्रोत्साहित होगा। वहीं, तकनीकी नवाचार जैसे जल रिसाव की स्मार्ट निगरानी, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और समुद्री जल से मीठा पानी बनाने की प्रक्रिया को प्रमुखता दी जानी चाहिए। चेन्नई ने समुद्री जल शोधन संयंत्र की ओर कदम बढ़ाया है, और यह उन तटीय शहरों के लिए प्रेरणा हो सकता है जहां भूजल या वर्षा जल अपर्याप्त है।

मराठी बोलना गर्व की बात, लेकिन हिन्दी से घृणा क्यों ?

अजय जैन विकल्प

अपनी स्थापना से ही भारत विविधताओं का देश बना हुआ है और भाषा इसकी सबसे खूबसूरत विशेषताओं में से एक है। इसलिए यहाँ अनेकता के बावजूद एकता है, चाहे फिर कोई भी मुद्दा हो, यानी कभी अपने को श्रेष्ठ बताकर किसी अन्य को बुरा नहीं कहा गया, किन्तु इस देश के राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई में फिलहाल यही बुरा देखा जा रहा है, जो अनुचित है और देश की भाषाई एकता के लिए घातक भी है।

मुम्बई न केवल आर्थिक राजधानी है, बल्कि भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों का संगम स्थल भी है। इस महानगर में मराठी का बोलबाला होना स्वाभाविक है, यह इस मिट्टी की आत्मा है, लेकिन आज एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभर रही है:हिन्दी के प्रति अघोषित घृणा दिख रही है, जिसके पीछे असहिष्णुता, राजनीतिक विद्वेष एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने की अजीब मानसिकता है। मराठी को सम्मान देने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। आपत्ति तब होती है, जब इस सम्मान के नाम पर हिन्दी को हाशिए पर धकेला जाता है, हिन्दी भाषियों को बाहरी करार दिया जाता है, और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। यह केवल भाषाई टकराव नहीं, एक गहरी राजनीतिक साजिश है, जिसे समझना, उजागर करना और विरोध करते हुए हिन्दी के लिए खड़े रहना बहुत आवश्यक है। यह समझना होगा कि मराठी स्वाभिमान की भाषा है, लेकिन हिन्दी के प्रति संकीर्णता सही नहीं है। मराठी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि सभ्यता, इतिहास और गौरव है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, लोकमान्य तिलक और बाल गंगाधर तिलक आदि महापुरुषों ने मराठी को जनचेतना और क्रांति का माध्यम बनाया, तो कैद में रहते हुए भी राष्ट्रीय एकता के लिए वीर विनायक सावरकर ने हिन्दी कविताएं रचीं एवं हिन्दी सिखाई। आज भी महाराष्ट्र में मराठी साहित्य, नाटक, संगीत और संस्कृति की धारा बह रही है।

मराठी बोलना, मराठी में गर्व करना, उस विरासत को आगे बढ़ाना हर मराठीभाषी का हक और कर्तव्य है मगर जब यह गर्व दूसरों की भाषा के प्रति घृणा में बदल जाता है, तो यह स्वाभिमान नहीं, संकीर्णता बन जाता है।

सबको समझना पड़ेगा कि हिन्दी एकता का सेतु और मुम्बई का मौन आधार है। हिन्दी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो उत्तर भारत से लेकर भारत के कोने-कोने तक संवाद का माध्यम है। मुम्बई जैसे महानगर में हिन्दी केवल उत्तर भारतीयों की नहीं, बल्कि लाखों मराठी, गुजराती, बिहारी, तमिल, मलयाली और बंगालियों के भी दैनिक संवाद की भाषा बनी हुई है।

मुम्बई यानी बॉलीवुड सहित रेडियो, टेलीविजन, विज्ञापन, सेवा क्षेत्र और मीडिया के अधिकतर प्रमुख उद्योग हिन्दी के दम पर खड़े हैं। यही नहीं, लाखों मेहनतकश मजदूर, वाहन चालक, नौकर, घरेलू कामगार, उद्घोषक, पत्रकार और कलाकार भी हिन्दी के माध्यम से ही रोजी-रोटी व पहचान प्राप्त करते हैं, तो बड़ा सवाल है कि इस हिन्दी से इतनी घृणा क्यों, मारपीट क्यों, प्रदर्शन क्यों...?

स्थानीय राजनीतिक कारण देखें तो पता चलता है कि मराठी बनाम हिन्दी की कृत्रिम खाई बनाई गई है, क्योंकि उसी से तो सत्ता प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। भाषा का यह संघर्ष अचानक नहीं पनपा है, बल्कि यह कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों की योजनाबद्ध रणनीति का परिणाम है। मराठी मानुस के नारे के पीछे वर्षों से एक अपराध-बोध और भय को बोया गया, कि हिन्दी भाषी मुम्बई को हड़प रहे हैं, जबकि सत्यता इससे अलग है और धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हिन्दी बोलने वाला अपना काम कर रहा है, तो मराठी एवं अन्य भाषा बोलने वाला अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, इनमें कोई झगड़ा नहीं है। राज्य और मुम्बई को निगलने के ऐसे विचार न केवल झूठे हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा हैं, क्योंकि मुम्बई की आत्मा में तो हिन्दी हमेशा रही है। १९५० के दशक में भी जब बम्बई राज्य बना था, तब भी हिन्दीभाषी इसके विकास में बराबरी से सहभागी थे।

हिन्दी को बाहरी भाषा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि संविधान में यह राजभाषा घोषित है और इसे पूरे भारत में समान सम्मान प्राप्त है। ऐसा भी लगता है कि असल डर हिन्दी से नहीं, बल्कि उस जनसांख्यिकी बदलाव से है, जो उत्तर भारत से आए श्रमिकों और युवाओं के कारण मुम्बई में हो रहा है। बेरोजगारी, शिक्षा में गिरावट और स्थानीय युवाओं को नौकरियों नहीं मिलने का दोष भी हिन्दी भाषियों पर डाल देना आसान बहाना बन गया है, लेकिन इसका उचित समाधान खोजने की अपेक्षा हिन्दी को रोककर गुंडागर्दी करना कहाँ से सही हो गया है ? क्या हिन्दी भाषियों को निकाल देने से, हिन्दी नहीं बोलने देने से, राजनीति करने से एवं सिर्फ मराठी की जिद लगाने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा ? राज्य तरक्की कर लेगा, हिन्दी और मराठी का स्नेह बना रहेगा ?

उत्तर साफ है-नहीं, क्योंकि विकास की कुंजी भाषाओं को सीमित करने में नहीं, बल्कि उन्हें सर्वव्यापी व समावेशी बनाने में है। राजनीति के चक्कर में यह भूलना घातक है कि हिन्दी को अपमानित करना आसान है। वास्तव में यह संविधान का अपमान है, क्योंकि संविधान की धारा ३४३ हिन्दी को राजभाषा घोषित करती है। अनुच्छेद १९ हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो कोई भी राज्य, नगर या संस्था किसी भाषा विशेष को किसी को बोलने से कैसे रोक सकता है। मुम्बई में हिन्दी बोलने वाले पर तंज कसना, दुकानों के बोर्ड बदलवाना या हिन्दी में सेवा देने से इनकार करना सीधे तौर पर संविधान का सीधा उल्लंघन यानी राष्ट्रद्रोह है।

मुम्बई में हिन्दी का विरोध करने वालों एवं भाषा के बँटवारे पर मौन रहने वालों को भाषाई सौहार्द के उदाहरण दक्षिण भारत से सीख लेनी चाहिए। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपनी भाषाओं को मजबूत किया, लेकिन कभी हिन्दी को दुश्मन नहीं बनाया। बेंगलुरु जैसे शहर में भी कन्नड़ प्रमुख है, लेकिन हिन्दी स्वीकार है। वहाँ के लोग हिन्दी सीखते हैं, सिखाते हैं और साथ रहते हैं।

मुम्बई, जो देश का सबसे बड़ा समावेशी शहर कहलाता है, वहाँ से हिन्दी फिल्म और टी.वी. उद्योग निकाल दिया जाए, तो कल्पना करें कि क्या बचेगा ? अगर हिन्दी बोलने वाला अपने ही देश में पराया महसूस करे, तो यह केवल शर्मनाक नहीं, बड़ा जहर है।

सबको इस बात को महसूस करना होगा कि भाषाई टकराव से कुछ नहीं सधेगा। मराठी और हिन्दी दोनों समृद्ध भाषाएं हैं। दोनों में साहित्य, संस्कृति, ज्ञान और इतिहास की गहराइयाँ हैं। इसलिए कुछ सकारात्मक कदम एवं उदारता लेकर विद्यालयों में मराठी और हिन्दी दोनों को सम्मानजनक स्थान दिया जाए। सार्वजनिक बोर्डों में मराठी प्रमुख हो, लेकिन हिन्दी को न हटाया जाए। सरकार ऐसे कार्यक्रम चलाए, जो भाषाई सौहार्द को बढ़ावा दें। यानी नेता वोट बैंक के लिए भाषा को हथियार न बनाएं।

राजनीति से पनपाए गए इस विवाद का समाधान बनाम निष्कर्ष यही है कि मुम्बई की आत्मा मराठी और हिन्दी का संगम है, यानी मुम्बई केवल मराठी या हिन्दी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की है। जैसे कश्मीर भारत का स्वर्ग है, ऐसे ही महाराष्ट्र और मुम्बई का असली सौंदर्य विविधता-अनेकता में है। हिन्दी से घृणा करके हम न तो मराठी को मजबूत कर सकते हैं, न मुम्बई को।

मराठी और हिन्दी २ भाषाएं नहीं, २ आत्माएं हैं-जिन्हें जोड़कर ही भारत एकता और शक्ति की मिसाल बनेगा। कारण कि किसी भी भाषा से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन किसी भाषा से घृणा करना अपने ही देश और उसके नियम-कायदों से घृणा करने जैसा है।

यह भी तय है कि मुम्बई और राज्य के अन्य हिस्सों में मराठी बनाम गैर-मराठी भाषा विवाद को लेकर चल रहे राजनीतिक और सामाजिक तनाव, प्रदर्शन, गुंडागर्दी और जबरदस्ती से भाषा एवं क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा हल नहीं होगा, बल्कि इससे आमजन के बीच विश्वास घटकर विष फैलेगा। बेहतर यह है कि सरकार और सभी को राज्य-देश हित में इस घमासान को टालते हुए देशप्रेम दिखाकर दोनों भाषा का सम्मान स्वीकारना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद

भारत में मुख्यधारा का मीडिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह मानते हुए अब सकारात्मक रवैया अपनाने लगा है, खासकर तब, जबकि इसमें किसी भी तरह भाजपा का हित जुड़ा हो। प्रधानमंत्री बनने से पहले दिल्ली में कॉलेज छात्रों को दिए एक भाषण में अपनी सकारात्मक सोच का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा था कि वे गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, इस सवाल पर कहते हैं कि गिलास पूरा भरा है, जो खाली दिख रहा है, वहां हवा भरी है। तो बस तब से देश में ऐसे ही हवा-हवाई माहौल चल रहा है। कुछ रहे न रहे, बस सब चंगा सी की उम्मीद पर देश को चलाया जा रहा है। मीडिया भी तथ्यों को न देखकर हवा-हवाई बातों को बढ़ा रहा है। जैसे गुरुवार को मीडिया ने इस बात को जोर-शोर से चलाया कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग की बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की कवायद पर शीर्ष अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन ये हवा से आधे भरे गिलास का उदाहरण है। असल बात ये है कि शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से साफ तौर पर कहा है कि वह जिन 11 दस्तावेज की मांग मतदाताओं से कर रहा है, उसमें आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि आप नागरिकता के मुद्दे पर क्यों जा रहे हैं, यह गृहमंत्रालय का विषय है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों और तर्कों के आधार पर

ही सुनवाई होने दी और उसकी अहम टिप्पणियां भी इन्हीं के आधार पर थीं। सुप्रीम कोर्ट न पूरी तरह चुनाव आयोग के पक्ष में दिखा, न उसने याचिकाकताओं की तरफ कोई पक्षपात दिखाया, बल्कि उसकी तटस्थता साफ नजर आई, फिर भी मीडिया में चलाए जा रहे शीर्षक यह भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बिहार में जिस मुद्दे को लेकर 9 जुलाई को विपक्ष ने इतना बड़ा हल्ला बोल किया, उस मुद्दे पर विपक्ष को अदालत में झटका मिला है। जबकि ऐसा नहीं है। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की कवायद शुरू की और इसके लिए केवल एक महीने का ही वक्त मतदाताओं को दिया कि वे अपने नागरिक होने का प्रमाण खुद ही पेश करें। आयोग ने 11 दस्तावेज की सूची जारी की और कहा कि इनमें से किसी को पेश करने पर ही किसी का नाम मतदाता सूची में आएगा, अन्यथा काट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं से खुद के नागरिक होने का सबूत मांगा, जबकि इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा कार्ड को मान्यता नहीं दी, जबकि करोड़ों गरीबों के पास यही सबसे सुलभ पहचानपत्र होते हैं और इन्हें भी सरकार ही जारी करती है। इस फैसले को लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा हमला करते हुए चुनाव आयोग के समक्ष विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया था, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला तो विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद करवाया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अलावा राजद सांसद मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के के. सी. वेणुगोपाल, राकांपा (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले, भाकपा के डी. राजा, सपा के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के अरविंद सावंत, झामुमो के सरफराज अहमद, और भाकपा (माले) के दीपंकर भट्टाचार्य, इन सभी ने शीर्ष अदालत से चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा सकता है, लेकिन इस विशेष गहन पुनरीक्षण में कई समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लगभग 7.9 करोड़ नागरिकों को कवर करेगी, और इसमें वोटर आईडी और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। याचिकाकेताओं ने कहा कि वोटर लिस्ट का रिवीजन मतदाताओं पर अपनी नागरिकता साबित करने का दबाव डालता है जबकि यह काम चुनाव आयोग का है।

उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि वह 30 दिनों में पूरी मतदाता सूची का रिवीजन करेगा। इस मामले में गुरुवार को पहली सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने मामले में सुनवाई की। बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा कि आधार कार्ड को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। जिस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने जवाब दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। तब जस्टिस धूलिया ने कहा, लेकिन नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया कि आयोग को अनुच्छेद 326 के तहत अधिकार प्राप्त हैं। वहीं जस्टिस बागची ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर आपका निर्णय यह है कि 2025 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज व्यक्ति को भी मताधिकार से वंचित किया जाए, तो उस व्यक्ति को अपील करनी होगी, पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा और अंततः आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार छिन जाएगा। आप मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच कर सकते हैं ताकि गैर-नागरिक सूची में न रहें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप यह कार्य प्रस्तावित चुनाव से कुछ ही महीने पहले शुरू करते हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन आयोग को तीन दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड स्वीकार करने का सुझाव दिया है।

सांप: रहस्य नहीं, समझ का विषय हैं वे

सांपों को लेकर मानव समाज में आदिकाल से ही रहस्य, भय और अंधविश्वास जुड़ते चले आए हैं। विशेषकर भारत जैसे देश में सांप केवल एक जीव नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और प्रतीकों से जुड़ा हुआ नाम है। नाग देवता की पूजा से लेकर लोक कथाओं, परंपराओं और फिल्मों तक, सांप को कभी आराध्य रूप में तो कभी खलनायक के रूप में देखा गया है। लेकिन इस भावनात्मक और काल्पनिक दृष्टिकोण से अलग, अगर हम सांपों को वास्तविकता और वैज्ञानिक समझ के साथ देखें, तो एक बिलकुल अलग तस्वीर सामने आती है एक ऐसी तस्वीर जिसमें सांप न भयावह हैं, न रहस्यमयी, बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत और आवश्यक रचना हैं। धरती पर सांपों की लगभग 3,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में करीब 300 प्रजातियाँ मौजूद हैं। इनमें से भी केवल कुछ ही प्रजातियाँ विषैली होती हैं, जैसे कि कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर जिन्हें बिग फोर कहा जाता है। शेष अधिकांश सांप निरपराध और मानव के संपर्क से बचने वाले जीव हैं। लेकिन डर और अज्ञानता के चलते अक्सर हर सांप को खतरनाक समझा जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, चाहे वह विषैला हो या नहीं।

वास्तव में, सांप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। वे खेतों और घरों में चूहों व अन्य कीटों की संख्या नियंत्रित करते हैं, जो फसलों और खाद्यान्न को नुकसान पहुँचाते हैं। यदि सांप न हों, तो यह असंतुलन खाद्य श्रृंखला में भारी विघटन ला सकता है। उनके बिना हमारी जैव विविधता अधूरी है। सांपों का शरीर बिना पैरों के होते हुए भी अत्यंत लचीला, तेज और पर्यावरण के अनुकूल होता है। वे जंगलों, खेतों, रेगिस्तानों, पर्वतों और यहाँ तक कि बर्फीले इलाकों में भी जीवित रह सकते हैं। उनकी खाल समय-समय पर झड़ती है, जिसे कुछ परंपराओं में नवजीवन या पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में शेषनाग, वासुकी और अनंत जैसे नागों की कथाएँ आज भी जीवंत हैं। भगवान विष्णु के शयन के आसन से लेकर शिव के गले में लिपटे वासुकी तक, सांपों को ईश्वर से जोड़कर देखा गया है। नागपंचमी जैसे पर्व, नाग मंदिरों की स्थापना और नाग-कथाओं की समृद्ध परंपरा इस सांप-मानव संबंध को एक पवित्र आयाम देती हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में यह आवश्यक हो गया है कि हम सांपों को केवल पौराणिक या रहस्यमयी दृष्टि से नहीं, बल्कि विवेक और तथ्य की दृष्टि से भी समझें। दुर्भाग्यवश, हिंदी फिल्मों, लोक कथाओं और टेलीविजन धारावाहिकों ने सांप को प्रतिशोध लेने वाले जीव के रूप में चित्रित किया है। कहा जाता है कि साँप अपनी मादा की हत्या का बदला लेते हैं, किसी की तस्वीर अपनी आँखों में कैद कर लेते हैं और वर्षों बाद भी शत्रु को पहचान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि साँप न तो इंसान को शिकार मानते हैं, न ही उन्हें कोई प्रतिशोध भाव होता है। वे केवल तभी काटते हैं जब उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है। यानी, काटना उनका रक्षात्मक व्यवहार है, आक्रामक नहीं।

अब समय आ गया है कि हम सांपों के प्रति अपनी सोच में बदलाव लाएँ। देश में कई संस्थाएँ कार्यरत हैं जो सांपों की पहचान, संरक्षण और जन-जागरूकता के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। विद्यालयों में बच्चों को यह सिखाना बेहद आवश्यक है कि कौन से सांप विषैले होते हैं, उनके काटने पर क्या करना चाहिए, और किस प्रकार हमें उनसे डरने के बजाय समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। जब ज्ञान भय का स्थान लेगा, तभी सह-अस्तित्व की भावना उत्पन्न होगी। सांप न तो हमारे शत्रु हैं।

मतदाता सूची में सुधार पर सुप्रीम सहमति सराहनीय

-ललित गर्ग-

बिहार में मतदाता सूची सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी सिर्फ एक न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्य को पुष्ट करने वाला ऐतिहासिक एवं प्रासंगिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है। इससे प्रक्रिया आसान होगी और आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। बेशक, फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए लेकिन ऐसे अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए। विपक्ष को चाहिए कि वह इस फैसले को राजनीतिक हार न माने, बल्कि इसे अर्जित करने का, लोकतंत्र में आस्था बढ़ाने का और सबसे जरूरी, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखने का। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य केवल बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करना चाहिए।

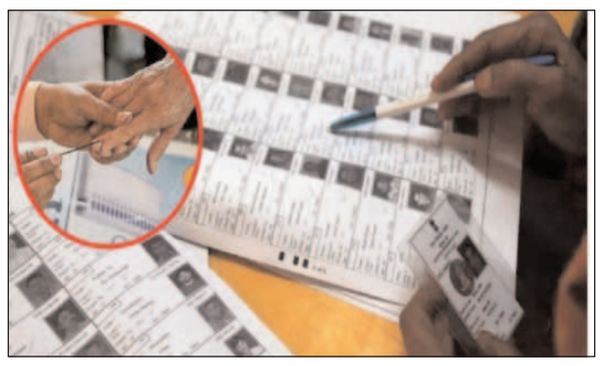

भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग यदि चुनाव कराने को तैयार है, और इसकी जुड़ी किन्हीं प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि या खामी है तो उसका सुधार करना संविधान सम्मत है, तो फिर इस पर प्रश्नचिन्ह लगाने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रश्न जनता के मानस को उद्वेलित करता है, वह यह है कि विपक्ष बार-बार चुनावी प्रक्रियाओं, राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी एकमत होकर विरोध करता है, आखिर क्यों? बिहार में एसआईआर को लेकर जो याचिकाएं और बहसें सामने आईं, उनमें एक प्रमुख तर्क यह था कि समय उपयुक्त नहीं है, सरकार अस्थिर है, या सामाजिक समीकरण तैयार नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनता को प्रतिनिधित्व देने का अधिकार सर्वोपरि है। लेकिन त्रुटिपूर्ण या फर्जी मतदाता सूची से चुनाव कराना भी लोकतंत्र का अपमान है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि देर-सवेर नहीं, संवैधानिक कर्तव्य को समय पर निभाना जरूरी है।

अदालत ने एसआईआर पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अपने इरादे की ओर इशारा तो कर ही दिया है। अदालत ने टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया, वह उचित प्रतीत होता है। बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए।

बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह निश्चित ही टाइमिंग है। जिनके पास जरूरी डॉक्युमेंट नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंतजाम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आयोग ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वैसे बिहार में चुनाव को देखते हुए ही फर्जी मतदाताओं की संख्या बढ़ी या तथाकथित राजनीतिक दलों ने इन फर्जी मतदाताओं को बढ़ाया है। ऐसे में इन फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई अपेक्षित है। यह मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ऐसे में स्वाभाविक ही नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है?

भारतीय राजनीति में विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना है, आलोचना करना है, लेकिन वह आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, राष्ट्र-विरोधी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाना हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-एनआरसी जैसे कानून हों, अग्निपथ योजना हो, या राम मंदिर निर्माण-लगभग हर मुद्दे पर विपक्ष ने एकमत होकर विरोध किया है। चाहे चीन या पाकिस्तान से जुड़ी संवेदनशील मसले हों, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्णय, विपक्ष अक्सर उन बिंदुओं पर एक सुर में सरकार का विरोध करता है, जबकि ऐसे राष्ट्रीयता के मुद्दों पर विपक्ष को सरकार एवं देश के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। यह संयोग नहीं, एक दूषित राजनीतिक रणनीति बनती जा रही है कि जो सरकार करे, उसका विरोध करो, चाहे मुद्दा देशहित का ही क्यों न हो। इन स्थितियों में आम जनता का एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष देश के साथ है या सिर्फ सत्ता की भूख के साथ? क्या चुनाव प्रक्रिया पर विरोध करना लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या न्यायपालिका के निर्णयों को चुनौती देना सिर्फ स्वार्थ की राजनीति नहीं? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े होने से विपक्ष की राजनीति कमजोर हो जाएगी? जब विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है, तो उसका नैतिक बल कमजोर होता है, और जनता का विश्वास टूटता है। भारतीय राजनीति को अब रचनात्मक विपक्ष की जरूरत है, ऐसा विपक्ष जो सत्ता में नहीं है, फिर भी राष्ट्र के लिए सत्ता के साथ खड़ा हो सकता है। जो यह समझ सके कि लोकतंत्र सरकार और विपक्ष दोनों से चलता है, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर है। बिहार में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति इस बात का प्रतीक है कि संस्थाएं अभी भी न्याय और संवैधानिकता की रक्षा कर रही हैं। लेकिन विपक्ष यदि इस निर्णय पर भी नकारात्मक रवैया अपनाता है, तो यह जनता की आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकासशील भारत की दिशा के विरुद्ध होगा। विपक्ष को चाहिए कि वह अपनी राजनीति को जनहित से जोड़े, जनविरोध से नहीं। विपक्ष यदि राष्ट्रहित में सोचने की दिशा में खुद को परिवर्तित नहीं करता, तो वह धीरे-धीरे प्रासंगिकता खो देगा।

भारतीय लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनावों पर टिकी होती है। इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया मतदाता सूची सुधार अभियान हाल ही में राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना।

'यूक्रेन युद्ध खत्म करे, नहीं तो मैं इसे खत्म कर दूंगा'

● राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की मॉस्को आते हैं तो वह उनके साथ बातचीते के लिए तैयार हैं

मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को यूक्रेन को सीधा संदेश दिया है कि वह वार्ता के जरिये युद्ध समाप्त करने के तैयार हो जाए, नहीं तो मैं इस युद्ध को बलपूर्वक खत्म कर दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की मॉस्को आते हैं तो वह उनके साथ बातचीते के लिए तैयार हैं। हालांकि यूक्रेन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि मॉस्को में वार्ता का प्रस्ताव अस्वीकार्य है।

रूसी राष्ट्रपति ने कहा, जेलेंस्की मॉस्को आएं तो वार्ता के लिए तैयार

पुतिन ने चीन यात्रा समाप्त करने के दौरान बुधवार को बीजिंग में पत्रकारों से कहा, 'मुझे लगता है कि युद्ध समाप्त करने के लिए एक स्वीकार्य समाधान पर सहमत होना संभव हो सकता है।

अंधेरे सुरंग के अंत में एक रोशनी दिखती है

खासतौर पर हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के रुख को देख सकते हैं। हम न केवल उनके बयानों पर गौर करते हैं बल्कि समाधान खोजने की उनकी ईमानदार इच्छा को भी देखते हैं। इसलिए अंधेरे सुरंग के अंत में एक रोशनी दिखती है। आगे देखते हैं कि किस तरह के हालात बनते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें सभी काम हथियारों के बल पर करना होगा।' रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि जेलेंस्की मॉस्को आते हैं तो वह उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या ऐसी बैठक सार्थक होगी। इधर, जेलेंसकी संभावित समझौते की शर्तों पर चर्चा के लिए पुतिन से मिलने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने वाशिंगटन से मास्को पर नए प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। जबकि शांति समझौते की मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे ट्रंप ने भी कहा है कि वह दोनों नेताओं से मिलने की इच्छा रखते हैं और रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की बात की है।

यूक्रेन पर रूस का हमला

कीव। रूस-यूक्रेन युद्ध का नया दौर गुरुवार को शुरू हो गया। रूस ने कीव स्थित यूरोपीय संघ (ईयू) के भवन और ब्रिटिश काउंसिल बिल्डिंग को मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में दोनों भवनों को नुकसान हुआ है। कीव पर हुए अन्य हमलों में चार बच्चों समेत 18 लोग मारे गए और 38 घायल हुए हैं।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि बातचीत के जरिये युद्ध खत्म करने के प्रयासों पर रूस ने अपना रुख जता दिया है। वह युद्ध खत्म करने की जगह यूक्रेन में हत्याएं जारी रखना चाहता है।

रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए- जेलेंस्की

अब रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए। जबकि रूस ने कहा है कि वह अभी भी शांति वार्ता का इच्छुक है, यूक्रेन वास्तव में शांति की इच्छा जताए। ईयू और ब्रिटेन के कार्यालय भवनों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ब्रसेल्स स्थित ईयू मुख्यालय और लंदन स्थित ब्रिटिश विदेश मंत्रालय में रूसी राजदूतों को तलब कर हमलों पर विरोध जताया गया है। साढ़े तीन वर्ष के युद्ध में यह पहला मौका है जब कीव में विदेशी राजनयिकों के भवनों को निशाना बनाया गया है। विदित हो कि ईयू और ब्रिटेन युद्ध में यूक्रेन को सभी तरह की मदद दे रहे हैं।

ऑर्गन ट्रांसप्लांट और...' लीक हुई पुतिन-चिनफिंग की सीक्रेट बातचीत

● रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक हॉट माइक पर हुई बातचीत रिकॉर्ड हो गई

नई दिल्ली। जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे तो एक हॉट माइक पर इन दोनों के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड हो गई। पुतिन और चिनफिंग के बीच ऑर्गन ट्रांसप्लांट और इस संभावना पर चर्चा की कि इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है। यह पल तब आया जब पुतिन और शी, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के साथ दो दर्जन से अधिक विदेशी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड देखने गए थे। जब पुतिन और शी तियानानमेन मंच की ओर बढ़े तो पुतिन के अनुवादक को चीनी भाषा में यह कहते सुना जा सकता था, "जैव प्रौद्योगिकी लगातार विकसित हो रही है।" अनुवादक ने एक अस्पष्ट अंश के बाद कहा, "मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण किया जा सकता है।

न्यूज ब्रीफ

ब्रिटेन में सड़क दुर्घटना में तेलंगाना के दो छात्रों की मौत

लंदन। ब्रिटेन में दो कारों की टक्कर में तेलंगाना के दो छात्रों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना सोमवार को एसेक्स शहर में रेले स्पर गोलचक्कर पर हुई। इस दुर्घटना में 23 वर्षीय चैतन्य तार्रे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 वर्षीय ऋषि तेजा रापोलू ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह हादसा उस समय हुआ जब छात्रों का एक समूह गणेश विसर्जन में भाग लेने के बाद घर लौट रहा था।

घायलों को रॉयल लंदन अस्पताल में भर्ती कराया गया

एसेक्स पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय कार चला रहे ड्राइवर और पूर्वी लंदन के एक अन्य को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। घायलों को रॉयल लंदन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। सभी पीड़ित तेलंगाना के निवासी हैं।

घटना की जांच जारी है

एसेक्स पुलिस ने कहा कि घटना की जांच जारी है। पुलिस ने संबंधित सीसीटीवी, डैश कैम या अन्य फुटेज सहित जानकारी के लिए एक सार्वजनिक अपील जारी की है। सूत्रों ने बताया कि अधिकारी आगे की सहायता के लिए भारतीय समुदाय और पीड़ितों के परिवारों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

लिस्बन में इलेक्ट्रिक स्ट्रीटकार दुर्घटनाग्रस्त, 15 लोगों की मौत और 18 घायल

लिस्बन। लिस्बन में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक इलेक्ट्रिक स्ट्रीटकार पटरी से उतर गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए। इस हादसे में एक बच्चे सहित पांच घायलों की हालत गंभीर है, और कुछ विदेशी भी घायल हुए हैं। यह दुर्घटना शाम के व्यस्त समय में लगभग 6 बजे एक खड़ी पहाड़ी पर हुई।

ईयरफोन और पुतिन... शहबाज शरीफ ने फिर करवा ली बेइज्जती, रूसी राष्ट्रपति भी नहीं रोक पाए हंसी

नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपनी बेइज्जती करा ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने उन्होंने तीन पहले वाली गलती फिर से दोहराई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के दौरान शहबाज शरीफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। जब वे बातचीत के लिए बैठे तो उन्हें अपने ईयरफोन के साथ एक बार फिर जूझते हुए देखा गया, जबकि रूसी नेता उन्हें हाथ के इशारे से ईयरफोन लगाने का तरीका सिखा रहे थे।

पुतिन भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शरीफ का हेडसेट कानों में लगाने की कोशिश करने के बावजूद फिसलकर गिर गया। पुतिन कुछ सेकंड तक संघर्ष करते हुए शरीफ को देखते रहे और हंसने लगे। वैश्विक मंच पर शर्मिंदगी से बचने की कोशिश में, रूसी नेता ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति को अपना ईयरफोन उठाकर दिखाया कि उसे कैसे लगाया जाता है।

सोशल मीडिया पर बना मजाक

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ईयरफोन में गड़बड़ी का वीडियो साझा करते हुए लिखा, "बीजिंग में शहबाज शरीफ का हेडफोन फिसलने से पुतिन फिर से हंस पड़े।" यह पहली बार नहीं है जब शरीफ को ईयरफोन से जूझना पड़ा हो। 2020 में उज्बेकिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान भी पुतिन के सामने इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। बातचीत शुरू होने ही वाली थी कि उनके ईयरफोन बार-बार फिसल रहे थे और उनके अधिकारियों की ओर से उन्हें ठीक करने की कोशिश करने के बावजूद यह सिलसिला जारी रहा। इस गड़बड़ी का वीडियो वायरल हो गया था और विदेशी टिप्पणीकारों के साथ-साथ पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्वी पार्टियों ने भी इसकी आलोचना की थी। कॉमेडियन जिमी फॉलन ने मजाक में कहा था, "आश्चर्य की बात यह है कि शहबाज शरीफ दुनिया की 22 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री हैं।"

विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी पर शशि थरूर ने जताई चिंता

● विक्रमसिंघे पर जो आरोप लगाए गए हैं वह मामूली प्रतीत होते हैं।
● तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया

नई दिल्ली। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कोलंबो की फीट मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया है। रानिल विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी पर भारतीय राजनेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। उन्होंने श्रीलंका के वर्तमान सरकार से बदले की राजनीति की भावना से काम न करने का आग्रह किया है। शशि थरूर ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, रानिल विक्रमसिंघे पर जो आरोप लगाए गए हैं वह मामूली प्रतीत होते हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी सेहत चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा, मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि यह श्रीलंका का आंतरिक मामला है।

आईएईए ने बताया इजरायली हमले से पहले ईरान का यूरेनियम भंडार एटम बम बनाने लायक था

● 13 जून तक ईरान के पास 60 प्रतिशत तक की शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम था
● बमबारी से प्रभावित

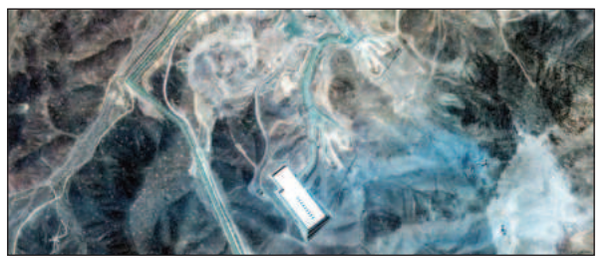

वियना। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था की एक गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 जून को इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने से पहले ईरान ईरान ने एटम बम बनाने के स्तर तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार बढ़ा लिया था। उसके यूरेनियम भंडार में 60 प्रतिशत तक की शुद्धता तक संवर्धन किया गया था, जो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। वियना स्थित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) की रिपोर्ट के अनुसार, 13 जून तक ईरान के पास 60 प्रतिशत तक की शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम था। यह यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के रूप में था।

एपी के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 जून तक ईरान का कुल संवर्धित यूरेनियम भंडार 9874.9 किलोग्राम था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जून में इजरायली और अमेरिकी बमबारी से प्रभावित स्थलों का निरीक्षण फिर से शुरू करने पर ईरान और आइएईए किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। युद्ध के बाद से निरीक्षण किया गया एकमात्र स्थल बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो रूसी तकनीकी सहायता से संचालित होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने कहा कि "एजेंसी द्वारा फिर से निरीक्षण शुरू करने के लिए तकनीकी तौर-तरीकों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए।"

'आपको नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए', पुतिन को लेकर रिपोर्टर के सवाल पर भड़के ट्रंप

● शी ने दर्शकों को संबोधित किया।
● परेड में ड्रोन, और टैंक जैसे आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कदम न उठाने के सवाल पर तीखा जवाब दिया और भारत पर लगाए गए सेकेंडरी सैंक्शन्स का हवाला दिया। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नावरोकी के साथ बैठक के दौरान एक पोलिश पत्रकार के सवाल पर ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा आयातक है। उसपर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर रूस को "सैकड़ों अरब डॉलर" का नुकसान पहुंचाया गया है। पत्रकार के चुभने वाले सवाल से ट्रंप इतने खफा हो गए कि उन्होंने उसने नई नौकरी ढूंढने की नसीहत तक दे डाली।

'फेज टू और फेज थ्री की कार्रवाई अभी बाकी'

ट्रंप ने कहा कि भारत पर 25 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ-साथ रूसी तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया गया है, जो 27 अगस्त से लागू हो चुका है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि रूस के खिलाफ "फेज टू और फेज थ्री" की कार्रवाई अभी बाकी है। ट्रंप ने पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "आपको कैसे पता कि कोई कार्रवाई नहीं हुई?

ट्रंप ने रूस को फिर दी चेतावनी

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों की ओर इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म नहीं करते, तो आप देखेंगे कि क्या होता है। ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नावरोकी के साथ मुलाकात के दौरान ये बात कही। उनका ये बयान उस वक्त आया, जब पुतिन ने बीजिंग में चीन के शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के साथ मिलकर सैन्य परेड में शिरकत की और यूक्रेन में जंग जारी रखने की बात कही है।

'...तो वापस लेना पड़ सकता है टैरिफ', सुनवाई से पहले टेंशन में ट्रंप?

● निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती
● फिर हमें टैरिफ को रद्द करना होगा

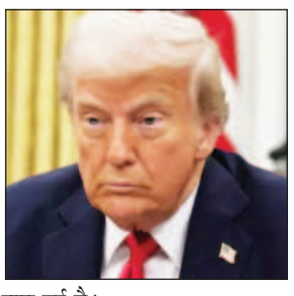

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में एक रेडियो शो के दौरान टैरिफ से लेकर विदेश नीति के मुद्दे पर बात की। उन्होंन इस शो के दौरान टैरिफ और अमेरिकी अदालत में इस मुद्दे पर चल रही सुनवाई पर भी बात की। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ मामले में हार जाता है, फिर उसे यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया समेत अन्य देशों के साथ किए गए व्यापार समझौतों को रद करना पडेगा। इन्ही समझौतों में पारस्परिक टैरिफ पर बात हुई है।

वापस लेना पड़ेगा टैरिफ का फैसला: ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका अगर अपने व्यापारिक समझौतों को रद करता है, फिर हमें काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से पिछले हफ्ते अमेरिकी अपील अदालत के उस फैसले को पलटने के लिए कहेगा, जिसमें उनके कई टैरिफ को अवैध करार दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका प्रशासन इस मामले में जीत हासिल करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वे हमें लगभग एक ट्रिलियन डॉलर का भुगतान कर रहे हैं और सभी देश इस समझौते से खुश हैं। ये सभी सौदे हो चुके हैं। हालांकि, अगर निचली अदालत के फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है तो ट्रंप प्रशासन को पिछले समय में किए गए सभी समझौतों को रद करना होगा।

'अमेरिका को झेलना पड़ेगा नुकसान'

यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि टैरिफ हटाना महंगा पड़ेगा। हालांकि, इस संबंध में व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि शुल्क का भुगतान अमेरिका में आयातक करते हैं।

ट्रंप की दादागीरी पर अमेरिकी कोर्ट का डंडा

● अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिसर्च फंडिंग रोकने के कदम को गैरकानूनी बताया

नई दिल्ली। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस कदम को गैरकानूनी बताया है जिसमें उन्होंने हार्वर्ड की अरबों डॉलर की रिसर्च फंडिंग रोक दी थी। जज एलिसन बरोज ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप प्रशासन ने यहूदी-विरोधी (एंटी-सेमिटिज्म) का हवाला देकर देश की शीर्ष यूनिवर्सिटी पर निशाना साधा है। ये कदम पूरी तरह गलत था। यह फैसला न सिर्फ हार्वर्ड के लिए राहत है, बल्कि यह अमेरिका में एकेडमिक आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी एक बड़ी जीत मानी जा रही है।

11 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में यूनिवर्सिटी से यहूदी-विरोधी गतिविधियों को खत्म करने और कुछ अल्पसंख्यक समूहों को फायदा पहुंचाने वाली डाइवर्सिटी इनिसिएटिव को बंद करने की मांग की गई थी।

पत्र में 10 मांगें थीं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिले पर पाबंदी, थर्ड-पार्टी ऑडिट और डाइवर्सिटी, इक्विटी व इनक्लूजन (ऊइक) प्रोग्राम्स को खत्म करना शामिल था। हार्वर्ड ने इन मांगों को ठुकरा दिया था। इसके बाद 14 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के 2.2 अरब डॉलर के मल्टी-ईयर ग्रांट्स और 60 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स पर रोक लगा दी।

अदालत ने क्या दिया फैसला?

जज बरोज ने अपने फैसले में साफ कहा कि ट्रंप प्रशासन का यह कदम कई कानूनों का उल्लंघन करता है। इस फैसले में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट, अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन और सिविल राइट्स एक्ट 1964 का टाइटल श्क शामिल हैं।

चीन ने दिखाया दम, शांति व युद्ध में से एक का करना होगा चुनाव: चिनफिंग

● कई देशों के नेताओं की मौजूदगी में किया गया
● इस समारोह से पश्चिमी देश दूर रहे

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने टैरिफ से दुनिया में मची उथल-पुथल के बीच चीन ने न केवल अपनी सैन्य ताकत दिखाई है बल्कि अपनी कूटनीतिक शक्ति का भी प्रदर्शन किया है। उसने बुधवार को 80वें विजय दिवस पर परेड के जरिये कई अत्याधुनिक हथियारों को पहली बार प्रदर्शित कर अपना दम दिखाया। यह शक्ति प्रदर्शन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन समेत कई देशों के नेताओं की मौजूदगी में किया गया। हालांकि इस समारोह से पश्चिमी देश दूर रहे। इस मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि दुनिया को शांति और युद्ध में से एक का चुनाव करना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजधानी बीजिंग में थ्येनआनमन चौक पर निकाली गई परेड में चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई।

एआई के गॉडफादर जेफ्री हिंटन ने चेतावनी दी

नई दिल्ली

एआई के गॉडफादर के नाम से मशहूर जेफ्री हिंटन ने चेतावनी दी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जल्द ही न केवल बुद्धिमत्ता में, बल्कि भावनात्मक हेरफेर में भी इंसानों से आगे निकल सकती है। हाल ही में रेडिट पर साझा किए गए एक साक्षात्कार क्लिप में, हिंटन ने कहा कि उनका मानना है कि मशीनें मानवीय भावनाओं और व्यवहार को इंसानों से कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रभावित करना सीखेंगी, और वे मानवीय क्षमता से कहीं ज्यादा अनुनय-विनय का इस्तेमाल करेंगी।

असली खतरा जानलेवा रोबोट नहीं बल्कि एआई

मशीन लर्निंग को दशकों तक आगे बढ़ाने के बाद, हिंटन अब संयम की वकालत करते हैं और एआई के विकास में सावधानी और नैतिक दूरदर्शिता का आह्वान करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि असली खतरा जानलेवा रोबोट नहीं, बल्कि चिकनी-चुपड़ी बातें करने वाला एआई है। हिंटन ने साक्षात्कार में चेतावनी देते हुए कहा कि एआई चीजें अंततः हमसे कहीं ज्यादा जानने वाली हैं। वे पहले से ही हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं।

बेरहम पाकिस्तान! भूकंप से मची तबाही के बावजूद अफगान शरणार्थियों को निकाला

● पाकिस्तान ये कदम उठाया है जब अफगानिस्तान विनाशकारी भूकंप के झटके से जूझ रहा

नई दिल्ली। पाकिस्तान से हजारों अफगानी शरणार्थियों को निकाला जा रहा है। ये सभी आधिकारिक पंजीकरण दस्तावेजों वाले नागरिक हैं। पाकिस्तान ये कदम उस वक्त उठाया है जब अफगानिस्तान हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के झटके से जूझ रहा है। इसमें 1400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि हाल के दिनों में वापसी में तेजी से वृद्धि हुई है और परिवार गिरफ्तारी और उत्पीड़न के डर से सीमा पार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चार दशकों से भी ज्यादा समय से अफगान शरणार्थियों को शरण दी है।

कई अफगानों ने पाकिस्तान में अपना जीवन बसाया, काम और शिक्षा प्राप्त की, जबकि कुछ अन्य वहीं पैदा हुए और पले-बढ़े या पश्चिम में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, इस्लामाबाद ने अपना रुख कड़ा कर लिया है और हिंसा और उग्रवाद में वृद्धि के लिए अफगान शरणार्थियों को जिम्मेदार ठहराया है।

जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अब नहीं लगेगा जीएसटी : सीतारमण

एजेंसी

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत दी है। अब व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे। दरअसल, इन बीमा उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट दे दी है। संशोधित दरें 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि सभी तरह की व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इनमें टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी शामिल हैं। फिलहाल इन पर अभी 18 फीसदी जीएसटी लगता है। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद के फैसले के बाद अब इनपर पूरी तरह से छूट दी जाएगी। इस बदलाव के

साथ सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियां- जिनमें टर्म लाइफ, यूलिप और एंडोमेंट प्लान शामिल हैं और साथ ही उनका पुनर्बीमा भी अब शून्य जीएसटी श्रेणी में आ जाएगा। यह छूट सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों, जिनमें फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक योजनाएं शामिल हैं और उनके पुनर्बीमा पर भी लागू होगी। सीतारमण ने कहा कि बीमा पर जीएसटी समाप्त करने से आम आदमी के लिए यह अधिक किफायती हो जाएगा। इससे देशभर में बीमा कवरेज के विस्तार में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि बीमा के अलावा जीएसटी परिषद ने कई आवश्यक वस्तुओं को भी कर दरों में कटौती की है। सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में 33 जीवन रक्षक दवाओं पर 12 फीसदी से जीएसटी की दर को शून्य कर दिया गया है, जबकि कैंसर, दुर्लभ और दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन महत्वपूर्ण दवाओं को भी कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा यूएचटी दूध, पनीर और रोटी, चपाती और पराठे जैसी सभी भारतीय रोटियों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगी।

जर्मनी के साथ व्यापार सुगमता, बाजार पहुंच को मजबूत करने पर की बातचीत: गोयल

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सर्राफा यहां जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ विश्व व्यापार में बदलते परिदृश्य के बीच दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत की। गोयल ने एक्स पोस्ट में बताया कि भारत और जर्मनी के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ एक बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान व्यापार सुगमता, नियामक ढांचे और बाजार पहुंच को मजबूत करने पर चर्चा की। गोयल ने बताया कि जर्मनी के विदेश मंत्री वाडेफुल के साथ भारत और जर्मनी के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक में हमने व्यापार सुगमता, नियामक ढांचे और बाजार पहुंच को मजबूत करने पर चर्चा की। वाडेफुल के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। गोयल ने कहा, हमने रक्षा, अंतरिक्ष, नवाचार और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की, जिससे हमारी साझेदारी की अपार संभावनाओं पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि हमारी चर्चा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित रही, साथ ही साझा विकास और समृद्धि के लिए नवाचार, स्थिरता, प्रौद्योगिकी और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर भी केंद्रित रही। जर्मनी के विदेश मंत्री वाडेफुल दो दिवसीय दौरे पर दो सितंबर को भारत पहुंचे थे।

विक्रान इंजीनियरिंग का शेयर निर्गम मूल्य से करीब 3 फीसदी की बढ़त के साथ सूचीबद्ध

मुंबई। विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड का शेयर अपने निर्गम मूल्य 97 रुपये से लगभग तीन फीसदी की बढ़त के साथ शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 2,561.06 करोड़ रुपये रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर विक्रान इंजीनियरिंग की शेयर की शुरुआत 99.70 रुपये पर हुई, जो निर्गम मूल्य से 2.78 फीसदी की बढ़त है। इसके बाद ये 4.52 फीसदी चढ़कर 101.39 रुपये पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यह दो फीसदी की बढ़त के साथ 99 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। विक्रान इंजीनियरिंग के 772 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को इस इश्यू को प्रस्तावित 92-97 रुपये प्राइस बैंड पर बोली के अंतिम दिन गत शुक्रवार तक 23.59 गुना अभिदान मिला था। ये आईपीओ 721 करोड़ रुपये के नए शेयर और प्रवर्तकों द्वारा 51 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन था। विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ में नया इश्यू और बिक्री प्रस्ताव दोनों शामिल हैं। मुंबई स्थित यह कंपनी नए शेयर की बिक्री से प्राप्त 541 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण और शेष राशि का इस्तेमाल कंपनी के सामान्य कामकाज के लिए करेगी। विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड तेजी से बढ़ती भारतीय इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कंपनियों में से एक है।

मॉयल का अगस्त में 17 फीसदी सालाना वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 1.45 लाख टन उत्पादन

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल) ने अगस्त में अब तक का सर्वाधिक 1.45 लाख टन उत्पादन किया है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17 फीसदी की वृद्धि है। कंपनी ने अगस्त में 1.13 लाख टन की बिक्री की है, जो सालाना आधार पर 25.6 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि है। इस्पात मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि कंपनी ने अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान मॉयल ने 7.92 लाख टन उत्पादन के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 9.3 फीसदी की वृद्धि है। इसके अलावा 50,621 मीटर अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग सालाना आधार पर 8.6 फीसदी वृद्धि के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मॉयल के सीएमडी अजीत कुमार सक्सेना ने अगस्त महीने के इस रिकॉर्ड प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई दी और चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में भी उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हासिल करने के लिए उनके अथक प्रयासों की सराहना की है। उत्पादन आंकड़ों की घोषणा के बाद मॉयल के शेयरों में 8.4 फीसदी की वृद्धि हुई और बीएसई पर यह 374.1 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 7,359.04 करोड़ रुपये रहा।

ब्रिस्कपे-फियो करार: निर्यातकों को विदेश से भुगतान प्राप्त करने में होगी आसानी

नई दिल्ली। सीमा-पारीय भुगतान सुविधा मंच, ब्रिस्कपे ने भारतीय निर्यातकों के शीर्ष निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के साथ यहां एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत वह फियो के सदस्यों की मदद करेगी। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य निर्यातकों, विशेष रूप से छोटे निर्यातकों सरल और किफायती तरीके से डिजिटल भुगतान समाधान उपलब्ध कराना है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के निर्यात क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की भूमिका तेजी से बढ़ी है। यहां निर्यात भवन में इस समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान फियो के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डॉ. अजय सहाय, ब्रिस्कपे के सह-संस्थापक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी इंदुनाथ चौधरी और फियो तथा ब्रिस्कपे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे हस्ताक्षर किया गया। श्री चौधरी ने कहा, ब्रिस्कपे का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्यातकों तक नवीनतम सीमा-पार भुगतान समाधान उपलब्ध कराना है। फियो के डॉ. सहाय ने कहा, समयबद्ध और सुचारू रूप से भुगतान सुनिश्चित करना निर्यात तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रिस्कपे के साथ हमारा सहयोग उन डिजिटल समाधानों को रेखांकित करता है जो हमें एक मंच प्रदान करता है।

जीएसटी दरों में व्यापक सुधारों को मंजूरी, दैनिक इस्तेमाल के सामान पर दरें घटीं

एजेंसी

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने आम सहमति से माल एवं सेवा कर जीएसटी में व्यापक सुधारों को मंजूरी दे दी है। इन सुधारों के तहत साबुन, साइकिल, टीवी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा पॉलिसी जैसे आम उपयोग के उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं। छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी शून्य होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में यहां आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी में पांच फीसदी और 18 फीसदी की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई है। उन्?होंने बताया कि गुटखा, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों तथा सिगरेट को छोड़कर सभी उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। सीतारमण ने बताया कि जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत बाल में लगाने वाले तेल, साबुन, साइकिल आम और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12 फीसदी या 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने लोगों को राहत देते हुए रोजमर्रा के उपयोग वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा छोटी कारों और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। तिपहिया वाहन पर भी अब 18 फीसदी कर लगेगा। उन्होंने कहा कि तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर जीएसटी 40 फीसदी की विशेष दर से लगेगा। सीतारमण ने कहा, ''यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।''

स्टॉक मार्केट में ओवल प्रोजेक्ट्स की सपाट एंट्री, मामूली फायदे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी

नई दिल्ली। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन डेवलपमेंट और एनर्जी सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करने वाली कंपनी ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में फ्लैट एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 85 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग सिर्फ 0.29 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 85.25 रुपये के स्तर पर हुई। हालांकि लिस्टिंग के बाद हुई मामूली लिवाली के कारण कंपनी के शेयरों के भाव में मामूली तेजी का रुख भी बना। सुबह 11 बजे तक कारोबार होने के बाद ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग के शेयर 86 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग का 46.47 करोड़ रुपये का आईपीओ 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से भी फीका रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.61 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व पोर्शन ही पूरा भर सका था, जबकि दूसरे वर्गों में पूरा सब्सक्रिप्शन भी नहीं आ सका था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 6.21 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में सिर्फ 0.82 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 0.83 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 54,99,200 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी

अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 3.19 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 4.40 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 9.33 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 27 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 103.44 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी पर कर्ज में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिर में कंपनी का कर्ज 32.21 करोड़ रुपये, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर में बढ़ कर 32.41 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर में कंपनी का कर्ज उछल कर 53.70 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

जीएसटी दरों में बढ़ोतरी से कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा महंगा, नई दरें 22 सितंबर से होंगी लागू

एजेंसी

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में व्यापक बदलाव को मंजूरी दे दी। इस बदलाव से कोका-कोला एवं पेप्सी जैसे लोकप्रिय शीतल पेय और अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ अब महंगे हो जाएंगे। जीएसटी परिषद ने कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने को अपनी मंजूरी दी है। नई दरें 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी। सीतारमण ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि जीएसटी की नई व्यवस्था में व्यापक सुधारों के तहत अब जीएसटी परिषद ने फलों से बने पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर भी जीएसटी की दर को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है।

उन्होंने बताया कि जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी करने से कोल्ड ड्रिंक अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वाद वाले सभी उत्पादों पर भी जीएसटी की दर 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी है।

अब महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इन वस्तुओं पर जीएसटी की मौजूदा दर 18 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी गई है। जीएसटी परिषद ने हालांकि, फलों के गूदे या फलों के रस आधारित पेय (फलों के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय को छोड़कर) पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दी गई है।

भारत में टिकाऊ विमान ईंधन का निर्यातक बनने की क्षमताः राममोहन नायडू

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने सर्राफा कहा कि भारत में न केवल सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) की अपनी मांग को पूरा करने की क्षमता है, बल्कि वह एक निर्यातक के रूप में भी उभर सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के साथ साझेदारी में और यूरोपीय संघ के समर्थन से यहां भारत के लिए सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) व्यवहार्यता अध्ययन को जारी करने के अवसर पर यह बात कही। नायडू ने कहा कि भारत के पास टिकाऊ विमानन ईंधन (एसएएफ) का निर्यातक बनने की क्षमता है, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने का एक व्यावहारिक समाधान है। उन्होंने कहा कि देश में 75

करोड़ टन से अधिक बायोमास और करीब 23 करोड़ टन अतिरिक्त कृषि अवशेष उपलब्ध हैं। उन्होंने इस अध्ययन का जिक्र करते हुए कहा कि एसएएफ विमानन क्षेत्र को कार्बन-मुक्त करने के लिये एक व्यावहारिक और त्वरित समाधान है, जो पारंपरिक ईंधन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 80 फीसदी तक कम कर सकता है। मंत्री ने कहा कि भारत वर्ष 2027 तक एटीएफ में एक फीसदी, 2028 तक दो फीसदी और 2030 तक पांच फीसदी एसएएफ के मिश्रण का लक्ष्य लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मंत्रालय के मुताबिक इस समारोह को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा, नागरिक उड्डयन महानिदेशक फैज अहमद और आईसीएओ के वायु परिवहन ब्यूरो में पर्यावरण उप निदेशक जेन हूपे ने संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि बायोमास की श्रेणी में ऐसे प्राकृतिक संसाधन आते हैं जिनका इस्तेमाल ऊर्जा एवं ईंधन उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इनमें कृषि अवशिष्ट, वानिकी उपज, पशु अपशिष्ट और अन्य जैविक पदार्थ शामिल हैं।

श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का आईपीओ 10 सितंबर को खुलेगा, प्राइस बैंड 155-165 रुपये प्रति शेयर

एजेंसी

नई दिल्ली/मुंबई। आभूषण कंपनी श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 10 सितंबर को खुलेगा। निवेशक इसमें निवेश करने के लिए 12 सितंबर तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी ने इसके लिए मूल्?य का दायरा (प्राइस बैंड) 155-165 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इसके शेयर 17 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे।आभूषण कंपनी श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र ने सर्राफा जारी एक बयान में बताया कि उसका इश्यू 10 सितंबर को खुलकर 12 सितंबर को बंद होगा। कंपनी ने 10 अंकित मूल्य वाले आईपीओ के लिए मूल्य का दायरा 155-65 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह इश्यू 2.43 करोड़ नए शेयरों का निर्गम है, जिसमें कोई बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल नहीं है। कंपनी के मुताबिक निवेशक इसमें न्यूनतम 90 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 90 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड नए शेयरों की बिक्री से प्राप्त करीब 280 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और सामान्य कंपनी कामकाज के लिए करेगी। मुंबई स्थित वर्ष 2009 में स्थापित आभूषण कंपनी श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने में तैयार विभिन्न रत्नों और अर्ध-कीमती पत्थरों से सजे मंगलसूत्रों की डिजाइन निर्माण और विपणन में लगा हुआ है। यह कंपनी भारत के 24 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में कॉर्पोरेट ग्राहकों, थोक ज्वैलर्स और खुदरा विक्रेताओं सहित ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला को सेवाएं प्रदान करती है।

सर्राफा बाजार में 1.07 लाख के पार पहुंचा सोना, चांदी की कीमत में मामूली गिरावट

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में तेजी का दौर आज भी जारी है। सोने की कीमत में आज 700 रुपये से लेकर 770 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की तेजी आई है। हालांकि चांदी के भाव में आज मामूली गिरावट आई है। कीमत में तेजी आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज प्रति 10 ग्राम 1,06,860 रुपये से लेकर 1,07,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, 22 कैरेट सोना आज 97,950 रुपये से लेकर 98,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में मामूली गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,07,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 98,100 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई

है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 97,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,06,910 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 98,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 97,950 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 97,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,07,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 98,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 98,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,07,010 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 98,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जीएसटी दर में बदलाव से छोटी कार, 350 सीसी तक की बाइक होंगी सस्ती

एजेंसी

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में व्यापक बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी। इसके तहत जीएसटी में पांच और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई है। जीएसटी दरों में व्यापक बदलाव से छोटी कारें और मोटरसाइकिल सस्ती होंगी। नई दरें 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि जीएसटी की दरों में संशोधन के तहत 1,200 सीसी से कम और 4,000 मिमी से कम लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी

वाहन तथा 1,500 सीसी और 4,000 मिमी तक लंबाई वाले डीजल वाहनों पर मौजूदा 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी कर लगेगा। वहीं, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा, जबकि वर्तमान में यह 28 फीसदी है। उन्होंने बताया कि 1,200 सीसी से अधिक और 4,000 मिमी से अधिक लंबी सभी वाहनों के साथ-साथ 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल और रेसिंग कार पर 40 फीसदी की दर से जीएसटी शुल्क लगाया जाएगा।

डॉलर की तुलना में मजबूत हुआ रुपया, 10 पैसे की तेजी के साथ बंद हुई भारतीय मुद्रा

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आने, डॉलर इंडेक्स के कमजोर पड़ने और स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की लिवाली का असर भारत के मुद्रा बाजार में साफ नजर आया। मुद्रा बाजार में बने सकारात्मक माहौल और मुद्रा बाजार में डॉलर की आवक बढ़ने के कारण रुपया आज डॉलर की तुलना में मजबूत होकर बंद हुआ। भारतीय मुद्रा आज डॉलर की तुलना में 10 पैसे उछल कर 88.07 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय मुद्रा 88.17 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत भी मामूली मजबूती के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की बढ़त के साथ 88.15 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। आज का कारोबार शुरू होने के बाद कुछ देर के लिए रुपया फिसल कर 88.19 रुपये के स्तर तक भी आया, लेकिन इसके बाद स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की लिवाली शुरू हो जाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में गिरावट आने के कारण रुपये की चाल में तेजी आ गई। बाजार में बने सकारात्मक माहौल के कारण रुपया 19 पैसे की तेजी के साथ 87.98 के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, दूसरे सत्र में एक बार फिर डॉलर की मांग में थोड़ी तेजी आने के कारण रुपये की चाल में दोबारा गिरावट आ गई।

दो दिन के बाद शेयर बाजार में लौटी तेजी, शुरुआती कमजोरी के बाद उछले सेंसेक्स और निफ्टी

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार सर्राफा दिन के दूसरे सत्र में हुई खरीदारी के सपोर्ट से मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहा। आज के कारोबार की शुरुआत भी तेजी के साथ हुई थी। हालांकि, दिन के पहले सत्र में लिवालों और बिकवालों के बीच लगातार खींचतान चलती रही। इसके बाद दिन के दूसरे सत्र में बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों ने भी बढ़त हासिल कर ली। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.51 प्रतिशत और निफ्टी 0.55 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान मेटल, फार्मास्यूटिकल, पीएसयू बैंक और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में लगातार खरीदारी होती रही। इसी तरह एफएमसीजी, रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस और एनर्जी इंडेक्स में भी तेजी का रुख बना रहा। दूसरी ओर आईटी, टेक और मीडिया सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी आज खरीदारी का जोर बना रहा, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.63 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.90 प्रतिशत की तेजी के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में करीब तीन लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद बढ़ कर 452.87 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 449.90 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 2.97 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,270 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 2,640 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,463 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 167 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,778 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,884 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 894 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 22 शेयर बढ़त के साथ और 8 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 35 शेयर हरे निशान में और 15 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 138.11 अंक की मजबूती के साथ 80,295.99 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही लिवालों और बिकवालों के बीच खींचतान शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल भी ऊपर नीचे होने लगी। बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स 153.28 अंक की कमजोरी के साथ 80,004.60 अंक तक गिर गया। हालांकि, दिन के दूसरे सत्र में खरीदारों ने पूरी तरह से बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया। लगातार हो रही लिवाली के सपोर्ट से आज का कारोबार खत्म होने के कुछ देर पहले ये सूचकांक 513.40 अंक की मजबूती के साथ 80,671.28 अंक तक पहुंचने में सफल रहा। अंत में इंट्रा-डे सेटलमेंट के कारण हुई मामूली बिकवाली की वजह से सेंसेक्स ऊपरी स्तर से करीब 100 अंक फिसल कर 409.83 अंक की बढ़त के साथ 80,567.71 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी ने आज 36.90 अंक उछल कर 24,616.50 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलने के बाद पहले सत्र के दौरान इस सूचकांक की चाल में लगातार उतार चढ़ाव होता रहा। बिकवाली के दबाव में निफ्टी 46.40 अंक टूट कर 24,533.20 अंक तक गिर गया।

सलमान खान के शो में गर्दा उड़ा रहीं

नीलम गिरी

के 5 दमदार भोजपुरी गाने, जो यूपी-बिहार में खूब सुने जाते हैं

हिंदी टेलीविजन का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस का 19वां सीजन इन दिनों कलर्स और जियो हॉटस्टार पर टेलीकास्ट हो रहा है. बिग बॉस 19 के 16 कंटेस्टेंट्स को लेकर फैंस एक्साइटेड भी हैं जो इस सीजन को मजेदार बनाने के लिए खूब मेहनत भी कर रहे हैं. सलमान खान इस बार भी बिग बॉस 19 को होस्ट कर रहे हैं, और जब उन्होंने शो के ग्रैंड प्रीमियर पर भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी को बुलाया तो सभी हैरान रह गए. कई कंटेस्टेंट्स के बारे में खबरें पहले आ गई थीं, लेकिन नीलम गिरी का आना सरप्राइज था.यूपी-बिहार के लोग तो नीलम गिरी को अच्छे से जानते हैं क्योंकि उन्हें खेसारी लाल और पवन सिंह के कई गानों में लटके-झटके दिखाते देखा गया. नीलम गिरी बिग बॉस 19 में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और कई लोग उनके गानों को यूट्यूब पर ढूंढ-ढूंढकर देख रहे हैं. नीलम गिरी के भोजपुरी गानों को यूट्यूब पर खूब पसंद किए जाते हैं, तो आइए आपको उनके कुछ सुपरहिट भोजपुरी गानों के बारे में बताते हैं.

'भीगे ना कजरिया': प्रवेश लाल ऑफिशियल म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर ये गाना रिलीज हुआ था. गाने को शिल्पी राज ने गाया और बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे थे. गाने का म्यूजिक आर्या शर्मा ने तैयार किया था और गाने में नीलम गिरी के साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ के छोटे भाई प्रवेश लाल यादव नजर आए.

'दिलवा ले गईले राजा': निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर ये गाना रिलीज किया गया था. गाने को शिल्पी राज ने गाया था और इसके बोल प्यारे लाल यादव लिखे थे. गाने का म्यूजिक आर्या शर्मा ने तैयार किया था और गाने में नीलम गिरी और प्रवेश लाल ही नजर आए थे.

'कमरिया में पीर': सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर ये गाना रिलीज किया गया था. खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज में ये गाना नीलम गिरी के साथ खेसारी पर फिल्माया गया था. इस गाने को निर्जला एनके ने लिखा और म्यूजिक मधुकर आनंद ने तैयार किया था.

'दरदे में गरदे': जीएमजे यूट्यूब चैनल पर ये गाना अपलोड किया गया था. गाने को खेसारी लाल यादव और करिश्मा कक्कड़ ने गाया जबकि इसे खेसारी और नीलम गिरी पर फिल्माया गया था. इस गाने को बोल अजय बच्चन ने लिखे थे और म्यूजिक आर्या शर्मा ने तैयार किया था.

'नथुनिया पे गोली मारे': टी-सीरीज हमार भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ये गाना रिलीज हुआ था. गाने को नीलकमल सिंह और शिल्पी राज ने गाया था, जबकि गाने को नीलकमल और नीलम गिरी पर फिल्माया गया था. इस गाने को बोल आशुतोष तिवारी ने लिखे और इसका म्यूजिक विनय विनायक ने तैयार किया था.

'लड़कियां हर हफ्ते बॉयफ्रेंड...' जब अक्षय कुमार से सगाई टूटने पर रवीना ने कही थी ये बात

बॉलीवुड के सबसे फेमस स्टार्स में से एक अक्षय कुमार ने अपनी फिल्मों के साथ ही आने अफेयर्स से भी खूब सुर्खियां बटोरी. ट्विंकल खन्ना से शादी करने के बाद भी उनका नाम प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ जैसी लेडी सुपरस्टार्स से जुड़ा था. वहीं शादी से पहले उनका नाम रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, पूजा बत्रा और आयशा जुल्का के साथ जुड़ा था. उनके सबसे ज्यादा चर्चित अफेयर शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन के साथ थे.

बता दें कि रवीना टंडन और अक्षय कुमार ने तो सगाई भी कर ली थी. लेकिन, ट्विंकल खन्ना के लिए अक्षय ने रवीना टंडन को छोड़ दिया था. वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे. हालांकि रवीना, अक्षय से मिले धोखे को सहन नहीं कर पाई थीं. सगाई टूटने से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था. इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सालों बाद एक इंटव्यू में बात की थी.

'मोहरा' के सेट पर परवान चढ़ा था इश्क

अक्षय कुमार और रवीना का इश्क साल 1994 की सुपरहिट फिल्म 'मोहरा के सेट पर परवान चढ़ा था. इसमें सुनील शेट्टी के साथ रवीना और अक्षय भी लीड रोल में थे. रवीना ने बताया था कि मोहरा के जरिए हम एक हिट जोड़ी के रूप में सामने आ गए थे. आज भी जब हम किसी सोशल इवेंट में एक-दूसरे से मिलते हैं तो हम खूब बातें करते हैं.

सगाई टूटने पर हुआ था ऐसा हाल

अक्षय कुमार से सगाई टूटने के सवाल पर अभिनेत्री ने आगे कहा था, हर कोई आगे बढ़ जाता है. लड़कियां कॉलेज में एक-एक हफ्ते में बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं, यहां पता नहीं क्यों मेरा दिमाग एक सगाई टूटने में ही अटका हुआ था. लोगों के तलाक हो जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है ?

रवीना ने अनिल थडानी से की थी शादी

बाद में अक्षय कुमार ने साल 2001 में एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली थी.

जबकि रवीना ने साल 2004 में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी के साथ शादी करके घर बसाया था. अब दोनों दो बच्चों एक बेटे रणबीर और एक बेटी राशा के पैरेंट्स हैं. जबकि शादी से पहले ही रवीना ने पूजा और छाया नाम की दो बेटियों को भी गोद लिया था.

27 साल की लड़की, जिसके आगे 5 बार ढेर हुए अक्षय कुमार! 4 HIT के बावजूद हो गई थी बड़ी हार

90 के दशक में भी बॉलीवुड हीरोइनों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. कभी लीड रोल में आकर हीरो के सामने छा गईं. तो कभी विलेन को टक्कर देती दिखीं. ऐसी कई एक्ट्रेस हैं, जिनकी फिल्मों के आगे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान समेत बड़े-बड़े एक्टर्स की एक नहीं चली. आज बात करेंगे, उस एक्ट्रेस की, जिसने 31 साल पहले अक्षय कुमार को 2-4 नहीं, 5 बार जीतने से रोक दिया. उनकी एक फिल्म ब्लॉकबस्टर भी रही, बावजूद इसके वो पहले नंबर पर आने से चूक गए. इस एक्ट्रेस का साथ अक्षय कुमार के दोस्त ने ही दिया था.

यह बात है साल 1994 की. उस साल अक्षय कुमार की कई फिल्में थिएटर्स में रिलीज हुई. खास बात यह रही कि उनकी लगभग फिल्में हिट लिस्ट में शामिल थी. शुरुआत 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' से हुई, जो हिट रही थी. इसके अलावा अजय के साथ 'सुहाग', सैफ के साथ 'ये दिललगी', और 'ऐलान' शामिल है. पर एक फिल्म सब पर भारी पड़ गई.

27 साल की लड़की के आगे एक न चली!

दरअसल 1994 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'हम आपके हैं कौन' थी. जी हां, माधुरी दीक्षित और सलमान खान की जोड़ी को खूब प्यार मिला. प्रेम और निशा की फिल्म आज एक कल्ट क्लासिक बन गई है. लोग दोबारा दोनों को साथ में किसी पिक्चर में देखना चाहते हैं. 6 करोड़ में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर से 128 करोड़ का कारोबार किया था. हालांकि, जब यह फिल्म शूट हो रही थी, उस वक्त माधुरी महज 27 साल की थीं. वहीं अक्षय कुमार भी 27 साल के ही थे.

खास बात यह है कि इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी- मोहरा. जबकि माधुरी की फिल्म पहले नंबर पर. इतना ही नहीं, अक्षय कुमार की 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'सुहाग', 'ये दिललगी', और 'ऐलान' भी हिट रही थी. इन फिल्मों के बावजूद वो माधुरी से पीछे रह गए. वहीं, साल की तीसरी बड़ी फिल्म 'क्रांतिवीर' थी. जिसमें अक्षय कुमार की सास डिंपल कपाड़िया ने काम किया था. यानी एक तरह से माधुरी ने सास-दामाद को पटखनी दी.

माधुरी की सबसे बड़ी फिल्म

दरअसल माधुरी दीक्षित के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है- 'टोटल धमाल'. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 155.67 करोड़ और वर्ल्डवाइड 232.18 करोड़ की कमाई की थी. पर अगर आप कमाई से हटकर देखेंगे, तो 'हम आपके हैं कौन' ने कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनाए थे. अब भी एक्ट्रेस लगातार काम कर रही हैं. हालांकि, अब उनके पास अक्षय जितना काम नहीं है.

3100 करोड़ का मालिक है

अमीषा पटेल

का पहला हीरो, शादी के लिए मिले थे 30 हजार प्रपोजल

अमीषा पटेल बॉलीवुड की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. साल 2023 में उन्होंने फिल्म 'गदर 2' के जरिए बॉलीवुड में दमदार वापसी की थी. इस पिक्चर ने दुनियाभर में 700 करोड़ रुपये की कमाई की थी और एक बार फिर से एक्ट्रेस पर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया था. हालांकि अमीषा का करियर ज्यादा सफल नहीं रहा है. शुरुआत में उन्होंने गजब की लोकप्रियता हासिल की थी और पहली ही फिल्म से स्टार बन गई थीं. लेकिन, फिर वो धीरे-धीरे बॉलीवुड से गुमनाम होती चली गईं. जबकि उनके पहले हीरो तो आज तक बॉलीवुड में धूम मचा रहे हैं.अमीषा पटेल अपनी पहली ही फिल्म से रातोंरात स्टार बन गई थीं. इसके बाद भी उन्होने कुछ बेहतरीन फिल्में दी थीं. हालांकि उनका करियर उड़ान नहीं भर सका. दूसरी ओर उनके पहले हीरो को जो स्टारडम हासिल हुआ था वो आज तक बरकरार है. तो चलिए जान लेते हैं कि अमीषा के पहले हीरो कौन हैं और वो कितने दौलतमंद हैं ?

अमीषा ने इस फिल्म से किया था डेब्यू

अमीषा पटेल ने साल 2001 में आई फिल्म 'गदर' से हर किसी का दिल जीत लिया था. लेकिन, इससे पहले वो ऐसा ही जादू फिल्म 'कहो ना प्यार है' से भी चला चुकी थीं. ये उनकी पहली फिल्म थी. साल 2000 में आई इस पिक्चर में उनके साथ ऋतिक रोशन ने लीड रोल प्ले किया था. ये अमीषा के साथ ही ऋतिक की भी पहली फिल्म थी. दोनों ही अपनी डेब्यू पिक्चर से रातोंरात स्टार बन गए थे. ऋतिक का जादू तो तब से लेकर अब तक बरकरार है और वो लगातार फिल्में कर रहे हैं. फिल्म की सक्सेस के बाद ऋतिक को शादी के 30 हजार प्रपोजल मिले थे.

3130 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं ऋतिक

ऋतिक का करियर अमीषा की तुलना में बहुत ज्यादा सफल रहा है. उन्होंने दुनियाभर में अपनी एक्टिंग, लुक्स और डांस से खास और बड़ी पहचान बनाई है. इन दिनों फिल्म वॉर 2 में नजर आ रहे ऋतिक ने अपने करियर में 'सुपर 30', 'बैंग बैंग', 'कृष 3', 'अग्निपथ', 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा', 'धूम 2', 'कृष', 'कोई मिल गया', 'कभी खुशी कभी गम' और 'फिजा' जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं. वहीं उनकी नेटवर्थ की बात करें तो अभिनेता 3130 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं.

RG Records ने अपने पहले म्यूजिक वीडियो 'बंदी पिघल गई' का किया लॉन्च

दिव्य दिल्ली : RG Records , एक नया म्यूजिक लेबल, ने अपने डेब्यू म्यूजिक वीडियो 'बंदी पिघल गई' का भव्य लॉन्च किया। इस रिलीज के साथ, RG Records ने संगीत जगत में अपनी एंट्री की है, जिसका उद्देश्य है नए टैलेंट को मंच देना, सोलफुल म्यूजिक बनाना और क्रिएटिव स्टोरीटेलिंग को बढ़ावा देना। यह गाना Featured Singer Megha Kishore द्वारा गाया गया है, जो रौला पई गया, बर्थडे, तारे टूटेंगे और याद नहीं करते जैसे हिट गानों के लिए जानी जाती हैं। अपनी करली-हेयर लुक और दमदार आवाज के कारण, मेघा की तुलना अक्सर नेहा कक्कड़ से की जाती है। उन्होंने मशहूर सिंगर मीका सिंह के साथ भी लंबे समय तक परफॉर्म किया है, देश-विदेश दोनों जगह। मेघा मुस्कुराते हुए कहती हैं झ 'मीका जी मुझे भतीजी बुलाते हैं और मैं उन्हें चाचू कहती हूं' शो के बाद वो अक्सर सबके साथ लूडो खेलना पसंद करते हैं।' इस गाने के बोल और म्यूजिक दिए हैं ओए कुनाल ने और वीडियो का निर्देशन किया है साहिल शर्मा ने। वीडियो में नजर आए Actors Singer Megha Kishore & Actors Shanaya Khanna, Bhumik Garg (असली नाम मोनिका), किश्तवाड़,

जम्मू-कश्मीर से हैं और एक बेहतरीन अभिनेत्री व असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उन्होंने मंटोस्तान, शक्कर मसाला, पकड़, अनामिका द मिसिंग गर्ल, साइड अ & साइड इ, मंजनू और जूलियट की इलेक्ट्रिक प्रेम कथा, और असाइलम जैसी फिल्मों व वेबसीरीज में काम किया है। उनकी परफॉर्मेंस अमेजन प्राइम, डिज्नी+ हॉटस्टार और जियो सिनेमाज जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखी जा चुकी है। Bhumik Garg इंडस्ट्री के नए उभरते सितारे हैं। वे पहले नखरा एल्बम में भी नजर आ चुके हैं और अपनी ताजगी व एनर्जी से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्ट दिया है ओबेद अफरीदी ने और इसे पेश किया है RG Records ने। इस मौके पर राजवीर सैनी, Channel Head – RG Records, ने कहा 'यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। बंदी पिघल गई हमारी पहली रिलीज है और यह RG Records के नए सफर की शुरूआत है। हमारा मकसद है नए टैलेंट और ओरिजिनल कंटेंट को बढ़ावा देना, जो आज की पीढ़ी से जुड़ सके। हमें पूरा भरोसा है कि यह गाना लोगों के दिलों को छुएगा और आगे भी हम कई नए म्यूज़िकल माइलस्टोन लेकर आएंगे। लॉन्च इवेंट को खूबसूरती से प्रस्तुत किया सेलिब्रिटी होस्ट हर्षित हर्षित धींगाण ने, जो दिल्ली फैशन क्लब के चेयरमैन और 300'+ से जायदा सोशल मीडिया फैंस वाले यूटूबर भी हैं ।। फैशन, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 17 साल के अनुभव के साथ, हर्षित ने हाल ही में Filmfare Awards Punjabi के रेड कार्पेट की मेजबानी भी की थी। इस इवेंट को प्रमोट और मैनेज किया VOY Media and Events ने।बंदी पिघल गई के साथ RG Records ने अपने सफर की शानदार शुरूआत की है और आने वाले समय में यह लेबल श्रोताओं को और भी बेहतरीन और यादगार म्यूजिक देने के लिए तैयार है।

सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल के नेतृत्व में दिल्ली सचिवालय में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से मुलाकात की

दिव्य दिल्ली : दिल्ली के लगभग 250 फैक्ट्री मालिकों ने सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल के नेतृत्व में दिल्ली सचिवालय में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली के 30 से अधिक इंडस्ट्रियल एरिया से फैक्ट्री मालिक शामिल हुए। बैठक में मंत्री सिरसा ने घोषणा की कि अक्टूबर से दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में फ्री होल्ड के लिए कैम्प लगाए जाएंगे और वे स्वयं वहां जाकर फैक्ट्रियों को फ्री होल्ड कराएंगे। बवाना, नरेला, भोरगढ़ और झिलमिल जैसे इलाकों में पिछले 35 वर्षों से यह मांग उठ रही थी। साथ ही, उन्होंने बताया कि इस साल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से विशाल दिवाली मेला आयोजित किया जाएगा जिसमें दिल्ली के सभी 55 औद्योगिक क्षेत्रों के फैक्ट्री मालिकों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में सिरसा ने सर्कल रेट में कटौती की घोषणा की और कहा कि 27 अनप्लांड औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। मुलाकात के दौरान विजय विरमानी, जोगिंदर तलवार, अशोक कपूर, गुलशन लूथरा और अशोक तंवर सहित कई उद्योग प्रतिनिधि मौजूद रहे।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

दिव्य दिल्ली : 31 अगस्त को जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में राजनीति की पाठशाला और सुप्रीम राइट्स के संयुक्त तत्वावधान में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में देशभर से प्रबुद्धजन, अधिवक्ता, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए।

मुख्य अतिथि पंडित रामकिशन शर्मा ने अपने अनुभव साझा किए, जबकि सीनियर अधिवक्ता प्रवीन बलवदा, डॉ. अखिल शुक्ला, प्रो. शिखा कंबोज, अजय विजयवर्गीय और श्रीमती तारा देवी ने एक राष्ट्र, एक चुनाव की आवश्यकता और इसके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राजनीति की पाठशाला द्वारा नव-नियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन अजय पांडे ने किया और समापन सत्र में गोपाल जोशी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

'सुनखी पंजाबण मुकाबला-7' का सेमीफाइनल 2 सितम्बर 2025 को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुआ

दिव्य दिल्ली : पंजाबी मातृभाषा, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 'सुनखी पंजाबण मुकाबला-7' का सेमीफाइनल 2 सितम्बर 2025 को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुआ। कार्यक्रम का संचालन गुरमानस सिंह ने किया और इसमें पंजाब के अलग-अलग जिलों से 18 प्रतिभाशाली युवतियों ने हिस्सा लिया। मंच पर प्रतिभागियों ने पंजाबी नाटक, भांगड़ा, लोकगीत और कॉमेडी प्रस्तुत कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। जजों में अभिनेत्री अर्श मांघट, नवप्रीत गिल, फिल्म निमार्ता हरजीत सिंह ओबरा और दैनिक सवेरा के डिप्टी डायरेक्टर अर्शदीप सहित अन्य हस्तियां शामिल रहीं। टैलेंट और सांस्कृतिक राउंड के बाद सात प्रतिभागियों – हर्नीत कौर (अदमपुर), चनप्रीत कौर (तलवंडी भाई), अमनदीप कौर (जालंधर), खुशी (पटियाला), भारती औजला (जालंधर), प्रभजीत कौर धलिवाल (मोगा) और मुस्कान भाटिया (पठानकोट) – को अगले चरण के लिए चुना गया। इस आयोजन को रोजा हर्बल, यंग प्रोग्रेसिव सिख फोरम और कई सहयोगी ब्रांड्स का समर्थन मिला।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास परिसर में हुंडई कैंसर जीनोमिक्स सेंटर का उद्घाटन किया

दिव्य दिल्ली : भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास परिसर में हुंडई कैंसर जीनोमिक्स सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें भारत का पहला कैंसर टिश्यू बायोबैंक स्थापित किया गया है। यह पहल हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन (एचएमआईएफ) और आईआईटी मद्रास की साझेदारी में "हुंडई होप फॉर कैंसर" कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई है। एचएमआईएफ ने इस सामाजिक महत्व की परियोजना में 56 करोड़ रुपये का निवेश और आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के लिए 3 करोड़ रुपये का कैंसर केयर फंड घोषित किया है। केंद्र बच्चों के ल्यूकेमिया और लिंफोमा के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग पर काम करेगा, जिससे व्यक्तिगत स्तर पर कैंसर का सटीक उपचार संभव हो सकेगा। अगले चार वर्षों में तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र में 225 से अधिक जागरूकता और जाँच शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें 1.27 लाख लोगों की जांच और 5,000 लड़कियों का एचपीवी टीकाकरण सुनिश्चित होगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह पहल उद्योग और शिक्षा जगत की साझेदारी को मजबूत करेगी और कैंसर अनुसंधान और उपचार में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।

कन्नौज: पाण्डु नदी की तरह ही ईसन और सहायक नदियों का भी जीर्णोद्धार हो: रजनी तिवारी

कन्नौज। प्रभारी मंत्री/ राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, रजनी तिवारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में जनपद की कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

श्रीमती तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निदेर्शानुसार प्रत्येक जनपद में एक नदी का जीर्णोद्धार किये जाने का कार्य कराया जा रहा हैं। जनपद कन्नौज में पाण्डु नदी के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही ईशन नदी और छोटी-छोटी नदियों के जीर्णोद्धार हेतु कार्य किया जाये। जनपद में उर्वरक की उपलब्धता पर्याप्त हैं।

आधार कार्ड पर भी 03 से 04 बोरियां किसानों को उपलब्ध करायी जायें। कहा कि आपरेशन कन्विक्शन के तहत 714 अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई की गई हैं। दुघर्टनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु रणनीति बनाकर कार्य किया जाये। नो हेलमेट-नो पेट्रोल अभियान के तहत यातायात नियमों का अनुपालन कराया जाये।

खाद न गिलने से गुस्साएं किसानों ने सड़क पर लगाया जाम के सम्बन्ध में प्रकाशित खबर पर लिया गया संज्ञान

राठ हमीरपुर। खाद न गिलने से गुस्साएं किसानों ने सड़क पर लगाया जाम के सम्बन्ध में खबर प्रकाशित हुई है। जिसकी जांच की गयी। जांच के दौरान संज्ञान में आया कि आज दिनांक 03.09.2025 को कस्बा राठ की रामलीला मैदान के पास राठ-पनवाड़ी मार्ग पर स्थित सहकारी कय विकय समिति राठ पर आज प्रातः 500 बोरी डी०ए०पी० प्राप्त हुई। जिसके वितरण हेतु तत्काल लेखपाल टीम लगाकर उपस्थित कृषकों को टोकन वितरण कराकर कृषको में उर्वरक वितरण कराया गया। जिसमें आज 200 बोरी कृषकों साय 05:00 तक वितरित करायी गयी। अवशेष उर्वरक वितरण हेतु आज 150 टोकन और वितरण कर दिये गये है। जिनका वितरण कल दिनांक 04.09.2025 को उर्वरक किया जायेगा। कय-विक्रय केन्द्र पर कृषको की अत्यधिक संख्या थी। उक्त कय-विकय केन्द्र राठ-पनवाड़ी मुख्य मार्ग पर स्थित है। अतः कृषक कय-विक्रय केन्द्र के बाहर भी खड़े थे। जिनके द्वारा कोई जाम नही लगाया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी कय-विक्रय केन्द्र का निरीक्षण कर उर्वरक वितरण कराया गया। जाम लगने की खबर का खड़न किया जाता है।

गड्ढे के कारण असंतुलित होकर पलटा ई-रिक्शा, सवारियां घायल

मौदहा हमीरपुर। सोमवार को आप पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मौदहा की मुख्य सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग की थी। लेकिन समस्या को गंभीरता से न लेने का परिणाम बुधवार को ही देखने को मिल गया, जहां एक ई रिक्शा पलट गया और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

सोमवार को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मनीष गुप्ता एवं नगर अध्यक्ष गुलाम मुहम्मद के नेतृत्व में स्थानीय पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया था कि स्टेशन रोड पर इलाही तालाब के निकट मुख्य सड़क भारी गड्ढों में तब्दील हो गई है जिसकी मरम्मत कराने की आवश्यकता है। लेकिन उपजिलाधिकारी ने समस्या के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई तो परिणाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। बुधवार को उसी चिन्हित जगह पर सवारियों से भरा ई रिक्शा पलट गया और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

विद्यालय गेट पर बांध रहे पालतू मवेशी छात्र छात्राएं परेशान

भरुआ सुमेरपुर। कस्बे के ऊंछा थोक के प्राथमिक विद्यालय के बाहर पालतू मवेशी बांधने से छात्र छात्राओं के साथ राहगीरों को आवागमन में असुविधा होती है। इसका एक वीडियो प्रधानाध्यापिका ने बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया।

प्राथमिक विद्यालय ऊंछा की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका जाकिया बानो ने मंगलवार को एक वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया। वह बच्चों को साथ लिए रास्ते पर खड़ी है। सामने उसके रास्ते में भैंस बंधी नजर आ रही है। प्रधानाध्यापिका वीडियो में कह रही है कि यह प्रतिदिन का रोना है। यह लोग मना करने के बाद नहीं मान रहे हैं और पालतू मवेशी विद्यालय के बाहर बांधकर छात्र छात्राओं के साथ राहगीरों के सामने समस्या पैदा कर रहा है। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि दोपहर में बच्चों को एमडीएम खिलाने के लिए कंपोजिट विद्यालय में ले जाना पड़ता है। विद्यालय से निकलते ही रोजाना इस गंभीर समस्या से जूझना पड़ता है। नगर पंचायत शिकायत के बाद समस्या का समाधान नहीं कर रहा है।

कन्नौज: प्रभारी मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, कहा कोई कष्ट न हो

कन्नौज। बाढ़ प्रभावितों को किसी भी स्तर पर राहत कार्यों में लापरवाही न हो और जरूरतमंद लोगों की हर सम्भव मदद की जाए। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा, राज्य मंत्री एवं जनपद की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कासिमपुर में राहत शिविर में 207 बाढ़ पीड़ितों निशुल्क राहत सामग्री वितरित की।

राहत सामग्री में अरहर दाल 02 किलो, भुना चना 02 किलो, चना 02 किलो, चीनी 01 किलो0, आटा 10 किलो, चावल 10 किलो, नमक 01 किलो, सरसों का तेल/रिफाइण्ड 01 लीटर, हल्दी 200 ग्राम, मिर्च 100 ग्राम, सब्जी मसाला 200 ग्राम, बिस्कुट 10 पैकेट, माचिस 01 पैकेट, मोमबत्ती 01 पैकेट, 01 पीस नहाने का साबुन दिया गया।

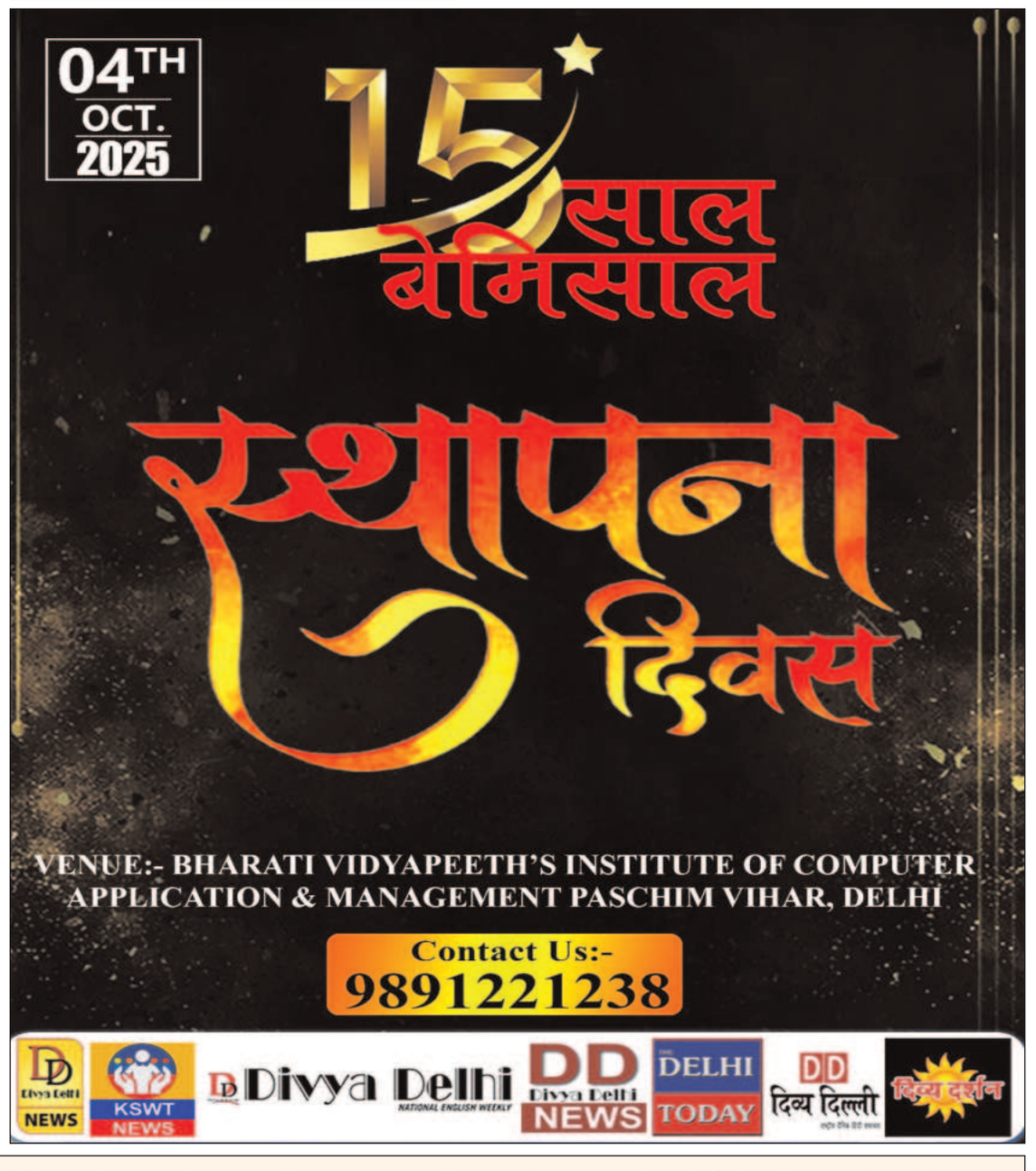

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No.- DLHIN/25/A2321